

Pradhan Mantri  
Jeevan Jyoti Bima Yojana



# एनडीए सरकार की 70 महत्वपूर्ण पहलें



सत्यमेव जयते

पत्र सूचना कार्यालय  
भारत सरकार

# राजग सरकार की 70 प्रमुख योजनाएं

## कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां

क्रम संख्या	योजना	नोडल मंत्रालय	आरंभ तिथि	उद्देश्य	उपलब्धियां
1.	<b>मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना</b>	कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का मंत्रालय	17.2.2015	पूरी तरह मुफ्त में मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करते हुए उत्पादकता सुधारने में किसानों की मदद करना, इसे हर तीन साल में नवीनीकृत किया जा सकता है। 2018 तक सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जाएंगे।	<ul style="list-style-type: none"><li>• 9 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए।</li><li>• 253 लाख मिट्टी के नमूने एकत्र किए गए और 248 लाख नमूनों का परीक्षण किया गया।</li><li>• दूसरे चरण (18.7.2017 तक) में 59 लाख नमूने एकत्र किए गए।</li><li>• मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना के अंतर्गत 2014-17 के दौरान राज्यों को 840.52 करोड़ रुपये जारी किए गए जबकि 2011-14 के दौरान 27.76 करोड़ रुपये जारी किए गए थे।</li><li>• मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत 2014-17 के दौरान राज्यों को</li></ul>

					<p>253.82 करोड़ रुपये जारी किए गए।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2014-17 के दौरान राज्यों को 8,572 मिनी लैब सहित 9,063 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए स्वीकृति दी गई जबकि 2011-14 के दौरान ऐसी महज 15 मंजूरीयां दी गई थीं।</li> </ul>
2.	<b>प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना</b>	<b>कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का मंत्रालय</b>	1.7.2015	<p>क्षेत्र स्तर पर सिंचाई में निवेश के अभिसरण को हासिल करना।</p> <p>खेतों में जल की भौतिक पहुंच बनाना और सुनिश्चित सिंचाई (हर खेत को पानी) के तहत खेती योग्य क्षेत्र में विस्तार करना।</p> <p>जल का अपव्यय घटाने और अवधि एवं सीमा दोनों में उपलब्धता बढ़ाने</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• पीएमकेएसवाई के तहत 28.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई के दायरे में लाया जाएगा।</li> <li>• 'हर खेत को पानी' का लक्ष्य हासिल करने के लिए पांच वर्षों के दौरान 50,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।</li> <li>• प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 5,189 करोड़ रुपये के बजट को बढ़ाकर 7,377 करोड़ रुपये किया गया।</li> <li>• दीर्घावधि सिंचाई कोष को 100 प्रतिशत बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपये (बजट 2017-18) किया</li> </ul>

				<p>(प्रति बूंद अधिक फसल) के लिए परिशुद्धता-सिंचाई एवं अन्य जल बचत प्रौद्योगिकी को अपनाना और खेतों में जल उपयोग की दक्षता बढ़ाना।</p> <p>पीएमकेएसवाई के तहत 28.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई के दायरे में लाया जाएगा।</p>	<p>गया।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 'प्रति बूंद- अधिक फसल' के लक्ष्य को हासिल करने के लिए 5,000 करोड़ रुपये का एक समर्पित सूक्ष्म सिंचाई कोष स्थापित किया जाएगा।</li> <li>• 'प्रति बूंद- अधिक फसल' के तहत 8.44 लाख हेक्टेयर क्षेत्र (मार्च 2017 तक) को सूक्ष्म सिंचाई के दायरे में लाया गया।</li> </ul>
3.	<b>प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना</b>	<b>कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का मंत्रालय</b>	13.1.2016	<p>प्राकृतिक आपदा, कीट एवं बीमारियों के कारण किसी भी अधिसूचित फसल के प्रभावित होने पर किसानों को व्यापक बीमा कवरेज प्रदान करना।</p> <p>नवोन्मेषी प्रथाओं को</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• फसल बीमा में केंद्र सरकार द्वारा अब तक की सबसे बड़ी वित्तीय सहायता। 2018-19 तक फसल बीमा कवरेज को 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की योजना।</li> <li>• खरीफ 2016 के दौरान 23 राज्यों द्वारा लागू, 401.54 लाख किसानों को बीमा कवर और 1,35,00,572.17 लाख रुपये की</li> </ul>

				<p>अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।</p> <p>अगले 2-3 साल में बीमित किसानों की संख्या को मौजूदा 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत करना।</p>	<p>बीमा राशि के साथ 392.82 लाख हेक्टेयर बीमित।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>रबी 2016-17 के दौरान अब तक 390.79 लाख किसानों को शामिल किया गया और 1,2958,383.40 लाख रुपये की बीमा राशि के साथ 379 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र बीमित।</li> </ul>
4.	<b>ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-एनएएम)</b>	<b>कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का मंत्रालय</b>	14.4.2016	<p>मार्च 2018 तक एक साझा ई-मार्केट प्लेटफॉर्म 'ई-एनएएम' के साथ 585 विनियमित बाजारों (एपीएमसी) को एकीकृत कर कृषि जिंसों के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार तैयार करना। ई-एनएएम के जरिये किसान अपनी फसल का बेहतर मूल्य प्राप्त करने में समर्थ होंगे। प्रत्येक</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>13 राज्यों में 455 मंडियां ई-एनएएम पर लाइव हैं।</li> <li>49.27 लाख से अधिक किसान और 93,093 व्यापारी इस प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत हैं।</li> <li>तमिलनाडु की 15 मंडियों के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।</li> <li>ई-एनएएम प्लेटफॉर्म पर 25,655.52 करोड़ रुपये मूल्य के कृषि उपज का लेनदेन (30.07.2017 तक) हुआ।</li> </ul>

				मंडी के लिए 75 लाख रुपये आवंटित।	
5.	<b>राष्ट्रीय गोकुल मिशन</b>	कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का मंत्रालय	16.12.14	स्वदेशी गोजातीय नस्लों को संरक्षित एवं विकसित करना।	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2017-18 के दौरान 80 करोड़ रुपये आवंटित।</li> <li>• 14 गोकुल ग्रामों की स्थापना की जा रही है और 41 बुल मदर फार्म का आधुनिकीकरण किया गया है।</li> <li>• 3,629 सांडों को प्राकृतिक सेवा के लिए लगाया गया।</li> </ul>
6.	<b>परंपरागत कृषि विकास योजना</b>	कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का मंत्रालय	2015-16	जैविक खेती को बढ़ावा देना।	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2015-18 के दौरान 10,000 क्लस्टर के तहत 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को जैविक खेती के दायरे में लाया गया।</li> <li>• राज्य सरकारों द्वारा अब तक 7,186 क्लस्टर विकसित।</li> </ul>

					<ul style="list-style-type: none"> <li>पूर्वोत्तर राज्यों के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला: 2015-18 के लिए 400 करोड़ रुपये आवंटित, 2015-17 के दौरान 156.79 करोड़ रुपये जारी।</li> </ul>
7.	<b>नीम कोटेड यूरिया</b>	रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय  उर्वरक विभाग		यूरिया की नीम कोटिंग।	<ul style="list-style-type: none"> <li>सरकार ने यूरिया की नीम कोटिंग को अनिवार्य किया।</li> <li>स्वदेशी यूरिया और आयातित यूरिया की 100 प्रतिशत नीम कोटिंग क्रमशः 1 सितंबर, 2015 और 1 दिसंबर, 2015 से प्रभावी।</li> <li>अत्यधिक सब्सिडी वाले यूरिया का गैर-कृषि कार्यों में इस्तेमाल घटकर लगभग नगण्य हुआ। यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित।</li> <li>नाइट्रोजन उपयोग दक्षता (एनयूई) में 5 से 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।</li> <li>मृदा स्वास्थ्य में सुधार।</li> <li>पौध संरक्षण रसायनों की लागत में कमी।</li> <li>कीटों और बीमारियों में कमी।</li> </ul>

					<ul style="list-style-type: none"><li>• धान की पैदावार में 5.79 प्रतिशत तक की वृद्धि।</li><li>• गन्ने की उपज में 17.5 प्रतिशत तक की वृद्धि।</li><li>• मक्का की उपज में 7.14 प्रतिशत तक की वृद्धि।</li><li>• सोयाबीन की पैदावार में 7.4 प्रतिशत तक की वृद्धि।</li><li>• तूर/लाल चने की पैदावार में 16.88 प्रतिशत तक की वृद्धि।</li><li>• पिछले तीन वर्ष यानी 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के दौरान प्रति हेक्टेयर यूरिया की खपत क्रमशः 152.53 किलोग्राम, 149.61 किलोग्राम और 136.44 किलोग्राम (अनुमानित) रही।</li><li>• यूरिया की नीम कोटिंग जो नाइट्रोजन रिलीज होने की गति को धीमी करते हुए प्रभावकारिता बढ़ाती है और संतुलित उर्वरीकरण के लिए किसानों के बीच जागरूकता अभियान के कुशल</li></ul>
--	--	--	--	--	--

					कार्यान्वयन के कारण खपत में कमी की प्रवृत्ति दिखी।
--	--	--	--	--	--

### अर्थव्यवस्था एवं आर्थिक सुधार

क्रम संख्या	योजना	नोडल मंत्रालय	आरंभ तिथि	उद्देश्य	उपलब्धियां
-------------	-------	---------------	-----------	----------	------------

8.	<b>प्रधानमंत्री जन धन योजना</b> <b>(पीएमजेडीवाई)</b>	<b>वित्त मंत्रालय</b>	28.7.2014	वित्तीय सेवाओं तक सभी परिवारों की पहुंच सुनिश्चित करने और सभी परिवारों के लिए व्यापक वित्तीय समावेशीकरण लाने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन।	<ul style="list-style-type: none"> <li>• पीएमजेडीवाई के तहत 19 जुलाई, 2017 तक कुल 29.18 करोड़ खाते खोले गए। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गए पीएमजेडीवाई खातों की संख्या 19.07.2017 तक 17.45 करोड़ रही।</li> <li>• शहरी क्षेत्रों में खोले गए पीएमजेडीवाई खातों की संख्या 19.07.2017 तक 11.73 करोड़ रही।</li> <li>• 22.53 रुपये कार्ड (19.07.2017 तक) जारी किए गए।</li> <li>• 15.77 करोड़ आधार को (असम और मेघालय को छोड़कर) सक्रिय बैंक खातों से जोड़ा गया।</li> <li>• जन धन खातों में कुल जमा = 64,777 करोड़ रुपये (19.07.2017 तक)</li> </ul>
----	---	-----------------------	-----------	--	---

9.	<b>प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई)</b>	<b>वित्त मंत्रालय</b>	8.4.2015	सूक्ष्म उद्यम क्षेत्र के विकास (विकास और पुनर्वित्त) के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।	<ul style="list-style-type: none"> <li>• तीन श्रेणियों- शिशु, किशोर एवं तरुण- के तहत बैंक से बिना गारंटी के आसान ऋण।</li> <li>• 21.7.2017 तक कुल 82.83 लाख खाते खोले गए।</li> <li>• कुल आवंटित रकम 42,395.95 करोड़ रुपये जिसमें से 40,100.3 करोड़ रुपये वितरित किए गए।</li> </ul>
10.	<b>विमुद्रीकरण एवं गरीब कल्याण योजना</b>	<b>वित्त मंत्रालय</b>	8.11.2016	8 नवंबर को 500 रुपये और 1,000 रुपये के नोट के विमुद्रीकरण के जरिये कालेधन के खिलाफ एक अभूतपूर्व जंग की ओर उठाया गया पहला कदम।	<ul style="list-style-type: none"> <li>• नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (एनसीआरबी) से उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि 9.11.2016 से 14.7.2017 की अवधि में राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के पुलिस द्वारा 11,24,04,980 रुपये अंकित मूल्य के 1,57,818 नकली भारतीय मुद्रा नोट्स (एफआईसीएन) की सूचना दर्ज की गई।</li> </ul>

11.	लकी ग्राहक योजना और डिजि-धन व्यापार योजना	नीति आयोग	25.12.2016	उपभोक्ताओं के लिए नकद पुरस्कार के माध्यम से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना और पुरस्कार प्रदान करना।	<ul style="list-style-type: none"> <li>देश भर के ग्राहकों और व्यापारियों सहित 16 लाख विजेताओं द्वारा 258 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि जीती गई।</li> </ul>
12.	डिजि-धन मेला				<ul style="list-style-type: none"> <li>डिजि-धन मेला: 25 दिसंबर 2016 को प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया, देश भर के 100 शहरों में 100 दिनों तक आयोजित।</li> <li>27 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में से प्रत्येक में कम से कम 100 ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में 15,000 संस्थान नकदीरहित हुए।</li> <li>शहरों, कस्बों और गांवों से 15 लाख से अधिक केंद्रों, मेलों के जरिये लाखों नए बैंक खाते खोलने के साथ-साथ नए आधार कार्ड बनाए गए।</li> </ul>

13.	जीएसटी	वित्त मंत्रालय	01.07.2017	एक राष्ट्र, एक कर - एक राष्ट्र, एक बाजार	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 जून/1 जुलाई 2017 की मध्य रात्रि में संसद के केंद्रीय कक्ष में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में जीएसटी को लॉन्च किया गया।</li> <li>• जीएसटी से सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के जुड़ने से वास्तव में यह 'एक राष्ट्र, एक कर' व्यवस्था बन गई है।</li> <li>• जीएसटी परिषद की अब तक 19 बैठक हो चुकी है।</li> <li>• जीएसटी परिषद में 18 श्रेणीय समूह अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं ताकि जीएसटी को सुचारू एवं प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके।</li> <li>• जीएसटी के विभिन्न पहलुओं को उजागर करते हुए 1 घंटे के सत्र वाले छह विशेष जीएसटी मास्टर क्लास का आयोजन किया गया और उन्हें 'जीएसटी की मास्टर क्लास' के तहत हिंदी और अंग्रेजी में 6 जुलाई से 8 जुलाई और 10 जुलाई से 12 जुलाई 2017 को डीडी</li> </ul>
-----	--------	-------------------	------------	---	---

					<p>नेशनल पर लाइव प्रसारित किया गया।</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• जीएसटी के लागू होने के साथ ही देश के 22 राज्यों में चेक पोस्ट समाप्त कर दिए गए हैं।</li><li>• वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने एक मोबाइल ऐप 'जीएसटी रेट्स फाइंडर' लॉन्च किया ताकि लोगों को एंड्रॉयड एवं आईओएस स्मार्टफोन पर विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए जीएसटी दरों की जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सके।</li><li>• दिल्ली के रेडियो एफएम चैनलों (निजी एवं एआईआर) पर आयोजित रेडियो जॉकी (आरजे) के लिए राजस्व सचिव द्वारा जानकारी दी गई।</li><li>• वित्त मंत्री द्वारा "अ केस स्टडी ऑन द बर्थ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) इन इंडिया- द जीएसटी सागा: अ स्टोरी ऑफ एक्ट्राऑर्डिनेरी नेशनल एम्बीशन" जारी किया गया।</li><li>• 18 जुलाई 2017 तक जीएसटीआईएन पंजीकरण की कुल संख्या 77,55,416</li></ul>
--	--	--	--	--	--

					<p>रही।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) द्वारा जीएसटी संबंधी सभी गतिविधियों का संकलन किया जा रहा है।</li> </ul>
14.	<b>प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)</b>	<b>वित्त मंत्रालय</b>	9.5.2015	<p>बैंक के खाते में 12 रुपये प्रतिवर्ष प्रीमियम के साथ 18 से 70 वर्ष के आयु वर्ग के गरीब एवं वंचित लोगों के लिए आकस्मिक मृत्यु एवं पूर्ण विकलांगता पर 2 लाख रुपये और आंशिक विकलांगता पर 1 लाख के जोखिम कवरेज के साथ बेहद सस्ती बीमा योजना प्रदान करना।</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>27.7.2017 तक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के तहत 1,02,020,812 लोगों का नामांकन हुआ।</li> <li>27.7.2017 को प्राप्त कुल दावों की संख्या 1,51,42 रही।</li> <li>27.7.2017 को 1,12,24 दावों को निपटाया गया।</li> <li>सिर्फ 12 रुपये वार्षिक प्रीमियम पर दुर्घटना बीमा।</li> </ul>
15.	<b>प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई)</b>	<b>वित्त मंत्रालय</b>	9.5.2015	<p>महज 330 रुपये के प्रीमियम के साथ 2 लाख रुपये का अक्षय जीवन बीमा कवर मुहैया कराते हुए 18 से 50 वर्ष के आयु वर्ग के गरीबों और वंचितों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था तैयार करना।</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>27.7.2017 तक पीएमजेजेबीवाई के तहत 31,556,755 लोगों का पंजीकरण हुआ।</li> <li>27.7.2017 तक 72,110 दावे प्राप्त हुए, जिनमें से 67,175 दावों को निपटाया गया।</li> <li>महज 330 रुपये वार्षिक प्रीमियम</li> </ul>

					पर जीवन बीमा।
16.	<b>अटल पेंशन योजना (एपीवाई)</b>	<b>वित्त मंत्रालय</b>	9.5.2015	18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के दैनिक मजदूरों अथवा अनौपचारिक क्षेत्र में काम कर रहे लोगों के लिए गारंटीयुक्त न्यूनतम मासिक पेंशन के माध्यम से बुढ़ापे में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना।	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 22 जुलाई, 2017 तक कुल ग्राहकों की संख्या 5,825,024 रही जो एपीवाई के तहत नामांकित हैं।</li> <li>• 2017-18 के दौरान एपीवाई के तहत 155 करोड़ (बीई) आवंटित किए गए।</li> </ul>
17.	<b>स्वर्ण मुद्राकरण योजना, सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम और इंडिया गोल्ड कॉइंस</b>	<b>वित्त मंत्रालय</b>	05.11.2015	घरेलू मांग को पूरा करने के लिए सोने के आयात पर देश की निर्भरता घटाना और भौतिक सोने की मांग में कमी लाना।	<ul style="list-style-type: none"> <li>• हाल में स्वर्ण मुद्राकरण योजना में संशोधन किया गया। प्रति वित्त वर्ष निवेश की सीमा को बढ़ाकर अब 4 किलोग्राम प्रति व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) के लिए 4 किलोग्राम और ट्रस्टों एवं सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य संस्थानों के लिए 20 किलोग्राम कर दिया गया है।</li> </ul>

					<ul style="list-style-type: none"> <li>• एसजीबी की तरलता और व्यावसायिकता में सुधार के लिए उपयुक्त बाजार बनाने की पहल की जाएगी।</li> <li>• सरकारी खाते में अब तक जमा रकम 4,769 करोड़ रुपये रही।</li> </ul>
--	--	--	--	--	---

### औद्योगिक विकास

क्रम संख्या	योजना	नोडल मंत्रालय	आरंभ तिथि	उद्देश्य	उपलब्धियां
-------------	-------	---------------	-----------	----------	------------

18	मेक इन इंडिया	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	25.9.2014	<p>भारत में अपने उत्पादों का विनिर्माण करने के लिए बहुराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहित करना। इस का उद्देश्य निवेश के जरिये अन्वेषण, निजी क्षेत्र की भागीदारी और विकास को प्रोत्साहित करना है।</p>	<p>भारत में निवेश एवं विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख राष्ट्रीय पहल के तौर पर मेक इन इंडिया के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के दायरे में तमाम सुधार किए गए हैं जिससे भारत में निवेश के लिए सकारात्मक माहौल बना है। अप्रैल 2014 से मार्च 2017 के बीच देश में 161 अरब अमेरिकी डॉलर एफडीआई प्राप्त होने के साथ ही एफडीआई प्रवाह में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इससे पता चलता है कि यह अप्रैल 2000 से मार्च 2017 तक भारत में हुए कुल एफडीआई प्रवाह का 33.2 प्रतिशत है। इसके अलावा मेक इन इंडिया की शुरुआत के बाद देश में एफडीआई इक्विटी प्रवाह में 62 प्रतिशत की शानदान बढ़ोतरी हुई है।</p> <p>देश जब गर्व के साथ आगे बढ़ रहा है तो दुनिया उसकी सफलता को स्वीकार कर रही है। 2017 में ए. टी भारत कीर्ने की एफडीआई विश्वास सूचकांक</p>
----	---------------	-----------------------------	-----------	--	---

				<p>में आठवें पायदान पर पहुंच गया। इसके अलावा भारत विश्व के सबसे आकर्षक निवेश गंतव्यों की सूची में पहले पायदान पर, वैश्विक स्तर पर 110 निवेश गंतव्यों के सर्वेक्षण में पहले पायदान पर, निवेश करने के लिहाज से दुनिया के बेहतरीन देशों में पहले पायदान पर और ग्रीनफील्ड एफडीआई के लिए शीर्ष स्थान पर रहा।</p> <p>तीन साल से भी कम समय में मेक इन इंडिया एक उच्च दृश्यमान और विश्वसनीय ब्रांड बन गया है, निवेश के लिए नए दरवाजे खुलने लगे हैं। इन सभी रैंकिंग से स्पष्ट तौर पर भारत की आर्थिक परिदृश्य में निवेशकों की आशावादिता झलकती है। सरकार भारत को एक निवेशक के अनुकूल गंतव्य बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। कारोबारी सुगमता के लिए उठाए गए कदमों से लेकर एफडीआई नीति के तहत किए गए सुधार तक,</p>
--	--	--	--	---

					<p>सभी मोर्चे पर सरकार की पहल को दुनिया को दुनिया भर में स्वीकार किया गया है। कारोबारी माहौल में सुधार की झलक भारतीय उद्योग परिसंघ के कारोबारी विश्वास सूचकांक में भी मिलती है। वित्त वर्ष 2016-17 की चौथी तिमाही के दौरान 64.1 के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया।</p>
--	--	--	--	--	--

## ऊर्जा

क्रम संख्या	योजना	नोडल मंत्रालय	आरंभ तिथि	उद्देश्य	उपलब्धियां
19	<b>पहल- एपीजी (डीबीटीएल) उपभोक्ता योजना के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण</b>	<b>पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय</b>	2.3.2016	एलपीजी सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी की रकम को सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खातों में भेजना और पूरी व्यवस्था में कुशलता एवं पारदर्शिता बढ़ाना।	<ul style="list-style-type: none"><li>• पहल की सफलता इस तथ्य से ही स्पष्ट है कि इसे विश्व की सबसे बड़ी नकद लाभ अंतरण योजना के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज की गई है।</li><li>• 15.11.2014 को 54 जिलों में शुरू किया गया और 1 जनवरी 2015 से 622 से अधिक जिलों में विस्तारित किया गया।</li><li>• अब तक करीब 18:36 करोड़ लोग लाभान्वित हो चुके हैं।</li></ul>

					<ul style="list-style-type: none"> <li>• विश्व का सबसे बड़ा लाभ अंतरण कार्यक्रम।</li> <li>• सब्सिडी के रूप में अब तक 53782 करोड़ रुपये का अंतरण सीधे खाते में हुआ।</li> <li>• 2014-17 से 29446 करोड़ रुपये सब्सिडी की बचत।</li> <li>• सबसे बड़ी लाभ अंतरण योजना के तौर पर इस योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया।</li> </ul>
20	<b>गिव अप सब्सिडी</b>	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	27.3.2016	स्वेच्छा से सब्सिडी छोड़ने के लिए आर्थिक रूप से संपन्न लोगों से अपील और गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन देने का वादा।	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 'गिव इट अप' अभियान - करीब 1.04 करोड़ उपभोक्ताओं ने सब्सिडी गिव अप किया। (1 मई 2017 के अनुसार)</li> <li>• 'गिव बैक' - बीपीएल परिवारों को 65 लाख कनेक्शन दिए गए।</li> </ul>

21	<b>प्रधानमंत्री</b> <b>उज्ज्वला</b> <b>योजना</b>	<b>पेट्रोलियम</b> <b>एवं</b> <b>प्राकृतिक</b> <b>गैस</b> <b>मंत्रालय</b>	1.5.2016	2016-17 से 2018-2019 तक 3 वर्ष के दौरान गरीबी रेखा (बीपीएल) से नीचे के परिवारों की महिलाओं को जमा मुक्त 5 करोड़ रसोई गैस (एलपीजी) कनेक्शन प्रदान करना।	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2.63 करोड़ बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए गए। (31 जुलाई, 2017 तक)</li> <li>• योजना का विस्तार पूरे देश में, अब 694 जिलों में।</li> <li>• 2016-19 के दौरान तीन वर्षों में 5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य।</li> </ul>
22	<b>ऊर्जा गंगा</b>		24-10-2016	<p>पांच राज्यों के 40 जिलों और 2,600 गांवों की ऊर्जा जरूरतों की पूर्ति होगी।</p> <p>तीन बड़े उर्वरक संयंत्र पुनर्जीवित होंगे, 20 से अधिक शहरों का औद्योगिकीकरण और 7 शहरों में शहरी गैस नेटवर्क का विकास होगा जिससे बड़ी संख्या में नौकरियां पैदा होंगी।</p>	<p>पहले चरण के निर्माण की स्थिति (31.07.2017 के अनुसार)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• गेल ने पाइपलाइन की 389.5 किलोमीटर लम्बाई के लिए आरओयू हासिल किया है, पाइपलाइन की 309.9 किलोमीटर लम्बाई में वेल्डिंग का कार्य पूरा हो चुका है और 246.0</li> </ul>

					<p>किलोमीटर पाइपलाइन को नीचे करके बिछाने का कार्य पूरा हो गया है.</p> <p>सीजीडी परियोजना</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• वाराणसी, भुवनेश्वर, कटक, कोलकाता, पटना, रांची और जमशेदपुर, यानी सभी 7 महानगरों में परियोजना संबंधी योजना बनाने और खरीद संबंधी क्रियाकलाप शुरू किए गए हैं! यह कार्य ग्रेटर कलकत्ता गैस आपूर्ति निगम के सहयोग से किया जा रहा है।</li><li>• वाराणसी, भुवनेश्वर और कटक में इस्पात और पीई पाइपलाइनों का निर्माण कार्य शुरू किया</li></ul>
--	--	--	--	--	---

					<p>गया है!</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• जेएचबीडीपीएल के दूसरे और तीसरे भाग की स्थिति</li><li>• आरओयू प्राप्त करने का काम प्रगति पर</li><li>• अनुमति के लिए आवेदन किया जा रहा है</li><li>• निविदा और पाइपलाइन आवंटित करने तथा बिछाने का काम प्रगति पर</li><li>• अन्य सामग्रियों की खरीद</li></ul>
--	--	--	--	--	---

					<p>का काम तेजी से किया जा रहा है</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>निर्माण कार्य दिसंबर 2017 से शुरू होने की संभावना</li> <li>दिसंबर 2020 तक कार्य पूरा होने का अनुमान</li> </ul>
--	--	--	--	--	--

### महिला सशक्तिकरण

क्रम संख्या	योजना	मंत्रालय	आरंभ तिथि	उद्देश्य	उपलब्धियां
-------------	-------	----------	-----------	----------	------------

23	बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	22.1.2015	<p>बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) योजना का समग्र दीर्घकालिक उद्देश्य देश में बाल लिंगानुपात (0-6 साल के आयु वर्ग के प्रति 1,000 लड़कों में लड़कियों की संख्या) में सुधार लाना और इन तात्कालिक उद्देश्यों के साथ लड़कियों के समग्र विकास के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करना है:</p> <p>क) लैंगिक चयन पर रोक,  ख) बेटियों को जीवन और सुरक्षा सुनिश्चित करना,  ग) बेटियों की शिक्षा सुनिश्चित करना।</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 161 जिलों में लागू, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में जन्म के समय लिंगानुपात (एसआरबी) में काफी अच्छी प्रगति दिखी है।</li> <li>• 161 जिलों में से 104 बीबीबीपी जिलों में एसआरबी में वृद्धि की प्रवृत्ति दिख रही है।</li> <li>• 119 जिलों ने पहली तिमाही के दौरान दर्ज एएनसी पंजीकरण के मुकाबले प्रगति दर्ज की है।</li> <li>• 146 जिलों में पिछले वर्ष के मुकाबले दर्ज कुल प्रसव मामलों में संस्थागत प्रसव की संख्या बढ़ी।</li> <li>• 2017-18 के लिए इस योजना के बजट आवंटन को बढ़ाकर 200 करोड़ रुपये किया गया।</li> <li>• मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने हर साल प्रत्येक जिले में 5 स्कूलों को जिलास्तरीय पुरस्कार प्रदान करने के लिए 5 लाख रुपये प्रति</li> </ul>
----	-----------------------------	------------------------------	-----------	---	---

					<p>जिला रकम आवंटित की।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>बहुक्षेत्रीय हस्तक्षेप अथवा जागरूकता अभियान के जरिये योजना के दायरे को 479 अन्य जिलों तक विस्तारित करने का प्रस्ताव है।</li> </ul>
24	<b>प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना</b>	<b>महिला एवं बाल विकास मंत्रालय</b>	1 जनवरी 2017 से पूरे देश में लागू	<p>i) वेतन नुकसान के लिए नकद प्रोत्साहन के रूप में आंशिक मुआवजा प्रदान करना ताकि महिला पहले जीवित बच्चे के प्रसव पूर्व और बाद पर्याप्त आराम कर सके।</p> <p>ii) उपलब्ध कराए गए नकद प्रोत्साहन से गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं (पीडब्लू और एलएम) के बीच बेहतर स्वास्थ्य व्यवहार पैदा होगा ताकि स्टंटिंग, वेस्टिंग एवं</p>	इस योजना के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश तैयार किए जा रहे हैं।

				कुपोषण संबंधी अन्य समस्याओं से निपटने में मदद मिल सके।	
25	हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए वन स्टॉप (जिसे 'सखी' कहा गया है)	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	4 मार्च 2015	हिंसा से प्रभावित महिलाओं को निर्भया कोष के जरिये चिकित्सा, कानूनी एवं मनोवैज्ञानिक सहायता सहित एकीकृत सेवाओं तक पहुंच के लिए सुविधा प्रदान करना। वन स्टॉप सेंटर को 181 एवं अन्य मौजूदा हेल्पलाइन के साथ एकीकृत किया जाएगा।	<ul style="list-style-type: none"> <li>• महज दो साल की छोटी अवधि के भीतर 148 ओएससी केंद्रों का परिचालन शुरू हुआ।</li> <li>• 21,000 से अधिक महिलाओं ने इन केंद्रों में मदद मांगी है।</li> </ul>
26	प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	4.11.2016	प्रत्येक माह की 9 तारीख को सभी गर्भवती महिलाओं को निश्चित, व्यापक और गुणवत्तापूर्ण प्रसव-पूर्व देखभाल मुफ्त उपलब्ध कराना। पीएमएसएमए सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर महिलाओं	<ul style="list-style-type: none"> <li>• प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में चलाया गया।</li> <li>• इस कार्यक्रम के तहत व्यापक सेवाओं के लिए पीएमएसएमए केंद्रों पर 40 लाख से अधिक प्रसवपूर्व जांच का आयोजन किया</li> </ul>

				को गर्भावस्था की दूसरी/तीसरी तिमाही में प्रसवपूर्व देखभाल सेवाओं के न्यूनतम पैकेज की गारंटी देती है।	<p>गया।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>पीएमएसएमए का आयोजन सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 11,000 से अधिक स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों पर किया जाता है।</li> <li>पीएमएसएमए के पोर्टल पर सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से 3,750 से ज्यादा स्वयंसेवकों को पंजीकृत किया गया है।</li> <li>1,400 से अधिक स्वयंसेवकों ने पीएमएसएमए के तहत सेवाएं प्रदान की हैं।</li> <li>पीएमएसएमए के तहत 2.70 लाख से अधिक उच्च जोखिम वाली गर्भधारण की पहचान की गई है।</li> </ul>
27	<b>मातृत्व लाभ योजना</b>	<b>श्रम एवं रोजगार मंत्रालय</b>	01.04.2017	भुगतानशुदा मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करने के लिए मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम 2017 को 1 अप्रैल 2017 से	<ul style="list-style-type: none"> <li>देश में करीब 2.8 करोड़ संगठित कार्य बल है जिनमें से 18 लाख महिलाएं हैं, जो लाभान्वित होंगी।</li> </ul>

				लागू किया गया है। इसमें 50 या इससे अधिक कर्मचारी वाले संस्थान में अनिवार्य तौर पर क्रेच की व्यवस्था और घर से काम करने का भी प्रावधान है। जननी और दत्तक माताओं दोनों के लिए पहली बार 12 सप्ताह के मातृत्व अवकाश का प्रावधान किया गया है।	
28	<b>प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना</b>	<b>वित्त मंत्रालय</b>	22.1.2015	कन्याओं के कल्याण को बढ़ावा देने और उन्हें एक सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने के लिए एक छोटी बचत जमा योजना।	<ul style="list-style-type: none"> <li>1,13,50,365 खाते खोले गए हैं और 30.6.2017 तक इस योजना के तहत 15,849.29 करोड़ रुपये से अधिक जमा कराए गए।</li> </ul>

### युवा एवं रोजगार

क्रम संख्या	योजना	नोडल मंत्रालय	आरंभ तिथि	उद्देश्य	उपलब्धियां
-------------	-------	---------------	-----------	----------	------------

29	<b>कौशल भारत</b>	<b>कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय</b>	15.7.2015	2022 तक विभिन्न कौशल में 40 करोड़ से अधिक लोगों को प्रशिक्षित करना। इसमें शामिल हैं- 'राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन', 'कौशल विकास एवं उद्यमिता के लिए राष्ट्रीय नीति 2015' और 'प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई)'।	<ul style="list-style-type: none"> <li>• पिछले 3 साल के दौरान अब तक कुल 2.6 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित किया जा चुका है जिनमें से 1.17 करोड़ लोगों को एमएसडीई कार्यक्रम के तहत कुशल बनाया गया है।</li> <li>• <u>प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना:</u></li> <li>• 30 लाख से अधिक उम्मीदवारों को पीएमकेवीवाई के तहत प्रशिक्षित किया गया है अथवा वे प्रशिक्षण ले रहे हैं और करीब 17 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करने के लिए 3,300 से अधिक प्रशिक्षण केंद्र खोलने का अतिरिक्त लक्ष्य रखा गया है।</li> <li>• 30 लाख में से 5,50,877 लोगों को प्रायर लर्निंग (आरपीएल) प्रोग्राम की मान्यता के तहत प्रशिक्षित किया गया है। इसके तहत व्यक्ति में मौजूद बुनियादी कौशल के मूल्यांकन के बाद उन्हें एक निश्चित स्तर के लिए प्रशिक्षित किया जाता है ताकि वे असंगठित क्षेत्र को औपचारिक तौर पर</li> </ul>
----	------------------	---	-----------	--	--

					<p>मदद कर सकें।</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• वर्तमान में पीएमकेवीवाई के तहत 34 क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।</li><li>• यह योजना 30 राज्यों और 7 केंद्रशासित प्रदेशों में लागू है।</li></ul> <p><u>प्रधानमंत्री कौशल केंद्र:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 514 जिलों के लिए 556 पीएमकेके आवंटित किए गए हैं जिनमें से 212 केंद्र पहले से ही परिचालन में हैं। मार्च 2018 के अंत तक हरेक जिला और संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को कवर करते हुए देश भर में 600 पीएमकेके खोलने का लक्ष्य है।</li></ul> <p><u>नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• इसके शुरू होने के 10 महीने के भीतर एनएपीएस के तहत 6.4 लाख से अधिक अप्रेंटिस और 32,281 संस्थान पंजीकृत किए गए हैं।</li></ul> <p><u>अकादमिक समतुल्यता की स्थापना:</u></p>
--	--	--	--	--	---

				<ul style="list-style-type: none"><li>• एनआईओएस द्वारा एक ब्रिज मॉड्यूल के माध्यम से कक्षा Xवीं या XIIवीं कक्षा वाले आईटीआई छात्रों की शैक्षिक समतुल्यता स्थापित की गई है। 1,027 आईटीआई छात्रों के पहले बैच के लिए परीक्षा का आयोजन दिसंबर 2016 में हुआ।</li></ul> <p><u>दीर्घकालिक कौशल विकास में क्षमता निर्माण:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 5 आईआईएस (इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ स्किल्स) प्रस्तावित हैं और आईआईएस कानपुर के लिए प्रधानमंत्री द्वारा कानपुर में 9 दिसंबर 2017 को आधारशिला रखी जाएगी।</li><li>• 12 राज्यों में विस्तृत एटीआई / एफटीआई की संख्या को बढ़ाकर 14 कर दी गई है। साथ ही, 5 नए महिला केंद्रित व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान (आरवीआईआई) भी खोले गए हैं।</li></ul>
--	--	--	--	--

				<p><u>अन्य उपलब्धियां</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 2015-17 के दौरान एमएसडीई कार्यक्रमों के तहत 1.17 करोड़ उम्मीदवार प्रशिक्षित हुए।</li><li>• औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में सीटों की संख्या में 44% की वृद्धि की गई।</li><li>• एनएसडीसी की अल्पकालिक शुल्क आधारित कौशल विकास मॉडल के तहत 2014 के मुकाबले 2017 में प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या में 600 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब तक 1 करोड़ से अधिक लोग प्रशिक्षित हो चुके हैं।</li><li>• 2016-17 के दौरान कौशल विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सीएसआर के तहत उद्योगों से 100 से अधिक के लिए प्रतिबद्धता।</li><li>• राज्यों में कौशल विकास को मजबूती देने के लिए विश्व बैंक द्वारा समर्थित परियोजनाएं- संकल्प (4,000 करोड़) और स्ट्राइव (2,200</li></ul>
--	--	--	--	--

					<p>करोड़)- शुरू की गई।</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• रोजगार में वैश्विक गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए इंडिया इंटरनेशनल स्किल सेंटर (आईआईएससी) को शुरू किया गया। फिलहाल ऐसे 14 केंद्र परिचालन में हैं और 2018 तक 100 केंद्र खोलने की योजना है। विभिन्न कौशल मानकों पर 11 देशों के साथ साझेदारी की गई है।</li><li>• युवाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री युवा योजना शुरू की गई।</li></ul> <p>ब्राजील में आयोजित वर्ल्ड स्किल्स 2015 में 8 उत्कृष्टता पदक हासिल किए, अबू धाबी में आयोजित वर्ल्ड स्किल्स 2017 में 28 लोगों की टीम भाग लेगी।</p>
--	--	--	--	--	--

30	स्टार्टअप इंडिया	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	16.1. 2016	टिकाऊ आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए स्टार्टअप के विकास के लिए अनुकूल माहौल तैयार करते हुए नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना।	<ul style="list-style-type: none"> <li>• स्टार्टअप इंडिया हब ने टेलीफोन, ईमेल और ट्विटर के जरिये स्टार्टअप द्वारा पूछे गए करीब 57,000 सवालों का जवाब दिया।</li> <li>• स्टार्टअप के साथ संवाद स्थापित करने के लिए ऑनलाइन लर्निंग एंड डेवलपमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया गया। यह मॉड्यूल स्टार्ट-अप इंडिया पोर्टल के जरिये उपलब्ध है।</li> <li>• मान्यता के लिए प्राप्त आवेदनों में से 2,306 में आवश्यक दस्तावेज थे और उन्हें डीआईपीपी द्वारा स्टार्टअप के रूप में मान्यता दी गई है।</li> <li>• कर लाभ प्राप्त करने के लिए 50 स्टार्टअप को आईएमबी द्वारा मंजूरी दी गई है।</li> <li>• स्टार्टअप इंडिया हब द्वारा इनक्यूबेशन एवं वित्तीय सहायता के लिए 410 से अधिक स्टार्टअप को संरक्षण प्रदान किया गया है।</li> <li>• स्थापित स्टार्टअप के लिए 10,000</li> </ul>
----	------------------	-----------------------------	------------	--	---

					करोड़ रुपये का 'फंड ऑफ फंड्स' स्थापित किया गया।
--	--	--	--	--	--

31	<b>स्टैंड-अप इंडिया</b>	<b>वित्त मंत्रालय</b>	5.4. 2016	महिलाओं और एससी एवं एसटी समुदाय के लोगों को 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये के बीच बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करते हुए उनमें उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना। कम से कम 2.5 लाख उद्यमी लाभान्वित होंगे।	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 30.7.2017 तक एसयूपीआई (जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाएं शामिल हैं) के तहत कुल 37,380 खाते।</li> <li>• कुल 8,035.34 करोड़ रुपये आवंटित किए गए जिसमें से 4,537.26 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं।</li> </ul>
32	<b>प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना</b>	<b>कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय</b>	15.7. 2015	युवाओं में रोजगार क्षमता बेहतर करने के लिए प्रमाणन के माध्यम से कौशल को मान्यता देना और औपचारिक तौर पर अल्पकालिक प्रशिक्षण प्रदान करना।	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 596 जिलों में 8,479 प्रशिक्षण केंद्र खोले गए।</li> <li>• 11 लाख से अधिक युवाओं का नामांकन हुआ।</li> <li>• 375 व्यापारों में प्रशिक्षण।</li> <li>• पीएमकेवीवाई (2015-2016) के तहत 19.85 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया और 2.49 लाख युवाओं को नियुक्तियां मिलीं। (अपडेटेड)</li> <li>• पीएमकेवीवाई (2016-2020) के लिए शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग, रिकॉग्निशन</li> </ul>

					<p>ऑफ प्रायर लर्निंग एवं स्पेशन प्रोजेक्ट्स के तहत 16.37 लाख लोगों के पंजीकरण का लक्ष्य रखा गया है जिसमें अब तक 2.72 लाख पंजीकरण हो चुके हैं। (अपडेटेड)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• पीएमकेवीवाई के तहत पंजीकृत कुल उम्मीदवारों में महिलाओं की संख्या करीब 50 प्रतिशत है।</li> <li>• पीएमकेवीवाई 1 के तहत एसटीएआर (संप्रग के तहत) के मुकाबले 40 प्रतिशत अधिक उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया।</li> </ul>
33	<b>नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रामोशन स्कीम</b>	<b>कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय</b>	19.08. 2016	<p>बुनियादी प्रशिक्षण की लागत को साझा करने और 25 प्रतिशत निर्धारित वजीफे की प्रतिपूर्ति के माध्यम से प्रशिक्षुओं को नियुक्त करने के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• योजना शुरू के बाद अब तक 4.3 लाख उम्मीदवार पंजीकृत हो चुके हैं।</li> </ul>

				करते हुए 2019-20 तक 50 लाख प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित करने के लक्ष्य के साथ अप्रेंटिसशिप को बढ़ावा देना।	
34	<b>खेलो इंडिया-खेल को बढ़ावा</b>	<b>युवा मामले और खेल मंत्रालय</b>	22 अप्रैल, 2016	<p>(i) खेल प्रतियोगिता का आयोजन</p> <p>(ii) खेल के लिए बुनियादी ढांचे का विकास</p> <p>(iii) प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान</p>	<p>(i) जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। सात राज्यों में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में 6978 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया।</p> <p>(ii) वर्ष 2016-17 में खेल संबंधी 18 बुनियादी परियोजनाएं मंजूर की गईं और वर्ष 2017-18 में खेल से जुड़ी 21 आधारभूत परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई थी (31.07.2017 तक)।</p> <p>(iii) इन प्रतियोगिताओं के दौरान कुछ प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान की गई।</p> <p>वर्ष 2016-17 में 118.10 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। चालू वित्त वर्ष 2017-18 के लिए 350 करोड़ रुपये के बजट का अनुमान है। इसके</p>

					<p>लिए अभी तक 132.17 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।</p> <p>नोट: खेलो इंडिया स्कीम खेल मैदानों के विकास, सामुदायिक कोचिंग, राष्ट्रीय स्कूल गेम, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल, प्रतिभा की पहचान, दीर्घावधि के लिए एथलीट विकास, विश्वविद्यालयों में उत्कृष्टता के विकास, महिला खेल, स्वदेशी / आदिवासी / ग्रामीण खेल, खेल शांति, पैरा स्पोर्ट्स आदि के लिए है। वित्त मंत्रालय ने ईएफसी को मंजूरी दी है। कैबिनेट नोट तैयार किया जा रहा है।</p>
--	--	--	--	--	---

35	<b>राष्ट्रीय युवा नेता कार्यक्रम (एनवाईएलपी)</b>		दिसंबर 2014	5 घटकों के साथ युवाओं में नेतृत्व गुणों को विकसित करने के लिए	<ul style="list-style-type: none"> <li>• नेहरू युवा केंद्र में 9.25 लाख युवा सक्रिय हैं और 12069 ब्लॉक स्तर पर युवा संसद का आयोजन किया गया। साथ ही ग्रामीण स्तर पर 80303 युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया।</li> <li>• 2013-14 में निर्धारित फंड 275-290 करोड़ को 500 करोड़ कर दिया गया।</li> </ul>
36	<b>प्रधानमंत्री युवा योजना</b>	<b>कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय</b>	9.11.2016	युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए यह योजना शुरू की गई है। अब युवा पीएमकेवीवाई 2.0 - प्रधानमंत्री युवा कौशल विकास योजना 2.0 (एमएसडीई)	प्रधानमंत्री युवा योजना (पीएम-युवा) <ul style="list-style-type: none"> <li>• अब तक, 306 परियोजना संस्थान [उच्च शिक्षा संस्थान (महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, प्रमुख संस्थान, पॉलीटेक्निक); स्कूलों; और उद्यमिता विकास केंद्रों] को सूचीबद्ध किया गया है।</li> <li>• इस मंत्रालय का लक्ष्य देश भर में 3050 परियोजना संस्थानों 2200 संस्थानों के उच्च शिक्षा, 300</li> </ul>

					<p>स्कूलों (10 +2), 500 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और 50 उद्यमिता विकास केंद्रों के माध्यम से उद्यमिता शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करना है। इसके तहत 14.5 लाख छात्रों को पांच साल (2016-17 से 2020-21) में प्रशिक्षित करना है।</p> <p>पीएमकेवीवाई में उद्यमिता उन्मुखीकरण पाठ्यक्रम का एकीकरण</p> <p>कौशल विकास के बाद उम्मीदवारों को उद्यमशीलता और स्व-रोजगार लेने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता को देखते हुए, एमएसडीई ने पीएमकेवीवाई में उद्यमिता उन्मुखीकरण कार्यक्रम (ईओपी) को एकीकृत किया है। मॉड्यूल उद्यमशीलता की अवधारणा और महत्व के बारे में विचार मुहैया कराता है। यह</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>मॉड्यूल पीएमकेवीवाई के तहत शामिल उम्मीदवारों की राज्यवार संख्या को कवर करेगा। वर्ष 2016-17 में, ट्रेनर्स कार्यक्रम के कुल 500 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।</p> <p>राष्ट्रीय उद्यमिता पुरस्कार</p> <p>पहली बार सरकार ने राष्ट्रीय उद्यमिता पुरस्कारों को 30 वर्ष से कम उम्र के सबसे पहले युवा पीढ़ी के उद्यमियों के प्रयासों और उपलब्धियों को पहचानने व पारिस्थितिक-प्रणाली बिल्डरों के असाधारण योगदान का जश्न मनाने के उद्देश्य से स्थापित किया है। इस पुरस्कार के केंद्र में युवाओं को रखा गया है। राष्ट्रीय उद्यमिता पुरस्कार 2016 को 30 जनवरी 2017 को आयोजित किया गया था। प्रतिष्ठित जूरी द्वारा चुने गए सात युवा उद्यमियों और विभिन्न राज्यों के चार असाधारण प्रतिष्ठित</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>पारिस्थितिकीय बिल्डरों को यह पुरस्कार मिला।</p> <p>पुरस्कारों का 2017 संस्करण शुरू हो गया है। देश भर में प्रविष्टियों के लिए प्रतियोगिता शुरू हो गई है।</p>
--	--	--	--	--	--

बुनियादी ढांचा (भौतिक और डिजिटल)

क्रम. सं.	योजना	नोडल मंत्रालय	शुभारंभ की तारीख	उद्देश्य	उपलब्धि
37	<b>सेतु भारतम</b>	<b>सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय</b>	<b>04.03.2016</b>	इसका उद्देश्य रेलवे ओवर ब्रिज/अंडर पास के निर्माण के जरिये 201 9 तक सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेल क्रॉसिंग से मुक्त करके सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना है। कार्यक्रम के तहत 20,800 करोड़ रुपये की लागत से 1 9 राज्यों में 208 आरयूबी / आरओबी का निर्माण किया जाना है। इसके अलावा, राष्ट्रीय राजमार्गों पर करीब 1500 पुराने और पहले से निर्मित पुलों की चरणबद्ध तरीके से मरम्मत की जानी है। इसकी लागत 30,000 करोड़ रुपये आएगी।	79 रेलवे ओवर ब्रिज के लिए 6507.23 करोड़ रुपये मंजूर हो चुके हैं। इस योजना के तहत पटना में गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु का पुनरूद्धार किया गया है। इसकी लागत करीब 1742 करोड़ रुपये आई। इसका काम चल रहा है। भारतीय पुल प्रबंधन प्रणाली (आईबीएमएस) की स्थापना की गई है ताकि पुलों की संरचनात्मक स्थिति को जाना जा सके और ताकि संरचना की गंभीरता के आधार पर समय पर मरम्मत और उसके पुनरूद्धार का कार्य किया जा सके। अब तक इसके तहत 1,62,022 से अधिक पुलों का पुनरूद्धार किया जा चुका है।

38	<b>चारधाम महामार्ग विकास परियोजना</b>	<b>सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय</b>	27.12.20 16	हिमालय में चार धर्म तीर्थयात्रा केंद्रों से कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए और इन केंद्रों की यात्रा को सुरक्षित, तेज और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए लगभग 900 किमी राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास किया जा रहा है। इसकी अनुमानित लागत करीब 12,000 करोड़ रुपये है।	<ul style="list-style-type: none"><li>• 3000 करोड़ रुपये की लागत वाली 17 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई और इसके लिए 31.12.16 को निविदा जारी की गई।</li></ul>

39	भारतमाला	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	भारतमाला परियोजना की औपचारिक शुरुआत होनी है।	इसे यह तटवर्ती / बंदरगाह क्षेत्रों, तीर्थ यात्रा केंद्रों, जिला मुख्यालयों और विकास के क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी सड़कों, आर्थिक गलियारों, अंतर गलियारों, फीडर मार्गों और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस मार्गों को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण को लेकर एक कार्यक्रम के रूप में परिकल्पित किया गया है।	<ul style="list-style-type: none"> <li>• इस योजना को अभी कैबिनेट से मंजूरी मिलनी बाकी है।</li> <li>• कार्यक्रम के पहले चरण में 24,800 कि.मी. की कुल लंबाई शामिल होगी। इसके पहले चरण के लिए 5,35,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी।</li> </ul>
40	उड़ान	नागरिक उड्डयन मंत्रालय	21 अक्टूबर 2016	क्षेत्रीय संपर्क योजना-उड़ान (उड़े देश का आम आदमी) का उद्देश्य चुनिंदा हवाई सेवा प्रदाता कंपनियों के जरिये किफायती दर पर दूरदराज के क्षेत्र में हवाई सेवा मुहैया कराना है। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय मार्गों पर सस्ते,	<ul style="list-style-type: none"> <li>• अभी तक सरकार ने पहले दौर में इसके तहत वायु सेवा शुरू करने को लेकर 5 चयनित एयरलाइंस के लिए 43 अनुरक्षित और अंडर-सर्विस एयरपोर्टों को जोड़ने वाले 128 रूट्स को शुरू किया है।</li> <li>• आरसीएस की उड़ानें छह हवाई अड्डों -</li> </ul>

				<p>आर्थिक रूप से व्यवहार्य उड़ान बनाना है ताकि छोटे शहरों में उड़ान सामान्य व्यक्ति के लिए सस्ती हो।</p>	<p>शिमला, नादेड़, कांदला, पोरबंदर, ग्वालियर और भटिंडा से शुरू की हैं।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>दूसरे दौर में आरसीएड-उड़ान जल्द ही शुरू होने की संभावना है।</li> </ul>
41	<p><b>उज्ज्वला डिस्कॉम एस्योरेंस योजना (उदय)</b></p>	<p><b>विद्युत मंत्रालय</b></p>	<p><b>20.11.2015</b></p>	<p>राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत वितरण कंपनियों के परिचालन और वित्तीय बदलाव को प्राप्त करने के लिए (डिस्कॉम) 27 राज्य, केंद्रशासित राज्य उदय से जुड़े हैं।</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>दक्षता में सुधार के बावजूद डीसीओसीओएम को बदलने के लिए सबसे व्यापक बिजली क्षेत्र में सुधार।</li> <li>पारदर्शी निगरानी प्रणाली के लिए उदय वेबसाइट का निर्माण किया।</li> <li>27 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उदय से जुड़े।</li> <li>राज्यों द्वारा जारी कुल बॉन्ड: 2,32,163 करोड़ रुपये (86.29%)</li> <li>एटी एंड सी नुकसान को 20.13% तक घटा दिया गया</li> <li>27 राज्यों / संघ शासित प्रदेशों में से 25 में टैरिफ संशोधन किया</li> </ul>

					<p>गया।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• फीडर मीटरिंग-शहर (100%), ग्रामीण (99%)</li> <li>• बिना जुड़े बिजली पाने वाले घर - 79%</li> <li>• ग्रामीण फीडर अलगवाव - 58%</li> <li>• ग्रामीण फीडर ऑडिट - 97%</li> </ul>
42	दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना(डीडीयूजीजेवाई)	विद्युत मंत्रालय	25.7.2015	विश्वसनीय, पर्याप्त एवं गुणवत्ता वाले बिजली आपूर्ति के साथ 100% ग्रामीण विद्युतीकरण और गांवों / बस्तियों और परिवारों को बिजली तक पहुंच प्रदान करने के लिए।	<ul style="list-style-type: none"> <li>• गांवों में बिजली पहुंची - 14,033 (76%)</li> <li>• बिजली से वंचित गांव - 3453 (19%)</li> <li>• निर्जन गांव - 966 (5%)</li> <li>• विद्युतीकरण घर - 13,58,63,298 (76%)</li> <li>• बिजली से वंचित घर - 4,31,72,940 (24%)</li> <li>• ग्रामीण घरेलू विद्युतीकरण में प्रगति के वास्तविक समय और पारदर्शी</li> </ul>

					ट्रेकिंग के लिए जीएआरवी II ऐप लॉन्च किया गया।
--	--	--	--	--	---

43	<b>सभी के लिए सस्ती एलईडी द्वारा उन्नत ज्योति (उजाला)</b>	<b>विद्युत मंत्रालय</b>	5.1.2015	मार्च 201 9 तक 77 करोड़ बल्बों को बदलने के लक्ष्य के साथ घरेलू उपभोक्ताओं को एलईडी बल्ब प्रदान करने के लिए	<ul style="list-style-type: none"> <li>• कुल वितरित एलईडी बल्ब - 25,25,64,221</li> <li>• प्रति वर्ष बिजली की बचत - 32,800 मिलियन किलोवाट</li> <li>• प्रतिवर्ष लागत की बचत - 13,120 करोड़ रुपये प्रति वर्ष</li> <li>• प्रतिवर्ष कार्बन डाईऑक्साइड में कमी - 2,65,67,818 टन</li> <li>• भारी मांग में कमी - 6,567 मेगावाट</li> <li>• मांग में एकीकरण की वजह से एलईडी बल्ब की खरीद में 310 रुपये (जनवरी 2014) की गिरावट के साथ यह 38 रुपये (जनवरी) में मिलने लगा।</li> <li>• कुल पंखा वितरण - 10,55,898</li> </ul>
----	---	-------------------------	----------	--	--

					<ul style="list-style-type: none"><li>• प्रति दिन बिजली की बचत - 4,09,160 किलोवाट</li><li>• प्रतिदिन लागत में बचत - 13,91,146 रुपये</li><li>• प्रतिदिन कार्बन डाईऑक्साइड में कमी - 336 टन कार्बन डाईऑक्साइड</li><li>• भारी मांग में कमी - 26 मेगावाट</li><li>• वितरित कुल ट्यूबलाइट - 29,43,341</li><li>• प्रतिवर्ष लागत की बचत - 43,83,22,491 रुपये</li><li>• प्रतिवर्ष कार्बन डाईऑक्साइड में कमी- 1,05,714 टन कार्बन डाईऑक्साइड</li><li>• भारी मांग में कमी - 59 मेगावाट</li></ul>
--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

44	स्ट्रीट लाइट नेशनल प्रोग्राम (एसएलएनपी)		3.5 करोड़ पारंपरिक स्ट्रीट लाइट की प्रतिस्थापन, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिवर्ष 9,000 मिलियन यूनिट की बचत होगी और सालाना 6.2 मिलियन टन कार्बन के कार्बन फुटप्रिंट में कमी होगी। इससे नगरपालिकाओं की कुल लागत बचत 5,500 करोड़ रुपये होगी।	<ul style="list-style-type: none"> <li>• कुल लगाए गए ट्यूबलाइट - 2,775,537</li> <li>• प्रतिदिन प्रति लाइट औसत ऊर्जा बचत - 0.385 किलोवाट</li> <li>• औसत ऊर्जा बचत प्रति दिन - 10,68,581.745 किलोवाट</li> <li>• जीएचजी उत्सर्जन कमी - 886.92 टन कार्बनडाईऑक्साइड</li> <li>• क्षमता की बचत - 97.14 मेगावाट</li> </ul>
----	--	--	---	--

45	<p>प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन</p>	<p>आयुष मंत्रालय</p>	<p>दिनांक 1 1 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा (यू एन जी ए) द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए सर्वसम्मति रूप से घोषित किया गया। 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग</p>	<p>राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों के बीच योग की प्रथा के बारे में जागरूकता सर्जन करना और इसकी रोधात्मक एवं प्रतिरोधात्मक गुणवत्ताओं का प्रचार-प्रसार करना ।</p>	<p>इस योजना की शुरुआत से लेकर आयुष मंत्रालय ने 3 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का सफलतापूर्वक आयोजन किया है। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस वर्ष 2015 में राजपथ, नई दिल्ली में, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन कैपिटल ग्राउंड, चंडीगढ़ में वर्ष 2016 में और तीसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन लखनऊ में रमाबाई अंबेडकर मैदान में वर्ष 2017 में आयोजन किया गया ।</p> <p>वर्ष 2015 में दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त किए गए थे नामतः 35985 प्रतिभागियों को शामिल करके सबसे बड़ा योग शिक्षण और एकल योग शिक्षण में भाग लेने वाले सबसे अधिक देशों (84) की भागीदारी हुई।</p> <p>दूसरे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने दो पुरस्कारों की घोषणा की</p>
----	---	----------------------	--	--	---

			<p>दिवस के रूप में मनाने का विचार सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिनांक 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में उनके भाषण के दौरान दिया गया था</p>	<p>- योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार</p> <p>प्रत्येक वर्ष लगभग 200 देश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन में भागीदारी करते हैं। सर्वेक्षण यह दर्शाते हैं कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा और इसके आयोजन के बाद से घरेलू रूप से योगा के समर्थकों में 30% की वृद्धि दर्ज की गई है जबकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर योग समर्थकों में 15% की वृद्धि दर्ज की गई है।</p>
--	--	--	--	--

46	प्रगति	कार्मिक एवं लोक शिकायत मंत्रालय	मार्च 25, 2015	प्रगति (अति सक्रिय गवर्नेंस और समयबद्ध कार्यान्वयन ) एक सूचना प्रौद्योगिकी आधारित कार्यक्रम है जिसके तीन उद्देश्य हैं नामतः शिकायत निवारण, कार्यक्रम कार्यान्वयन और परियोजना मॉनिटरिंग ।	शिकायतों के लिए प्रधानमंत्री पोर्टल को सीपीजीआरएएमएस के साथ एकीकृत किया गया है और सीपीजीआरएएमएस के अंतर्गत श्रेणियों को भी बढ़ाया गया है जिससे कि बेहतर वर्गीकरण किया जा सके।  कृपया उपलब्धियों पर नवीनतम आंकड़ा अद्यतन कीजिए।
----	--------	--	-------------------	--	--

47	डिजिटल इंडिया	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	1.7.2015	<p>ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करके और इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाकर देश के नागरिकों को सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रदान करना, डिजिटल इंडिया तीन मुख्य घटकों से मिलकर बना है - डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, सेवाओं की डिजिटल रूप से सुपुर्दगी और डिजिटल साक्षरता</p>	<p>भारत नेट परियोजना के लिए आवंटन को वर्ष 2017 18 में 10,000 करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया गया है। 1,55,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल ग्राम पंचायतों को जोड़ने के लिए बिछाई गई है। देश में 82 प्रतिशत से भी अधिक भारतीय लोग दूरसंचार सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।</p> <p>वर्ष 2017 - 18 के अंत तक 1, 50, 000 से भी अधिक ग्राम पंचायतों में वाईफाई हॉटस्पॉट और कम दरों पर डिजिटल सेवा तक पहुंच के साथ ऑप्टिकल फाइबर पर हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी।</p> <p>कृपया उपलब्धियों का नवीनतम आंकड़ा अद्यतन कीजिए?</p>
----	---------------	--	----------	--	--

48	<b>भारत नेट हाइ - वे से आई - वे और ग्रामीण ब्रॉडबैंड</b>	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय		गांव में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क कनेक्टिविटी	<p>भारतनेट परियोजना के अधीन, 1,07,066 ग्राम पंचायतों में 2.40 लाख किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई गई है , 1,00,322 ग्राम पंचायतों में 2.20 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर खींचा गया है और 30 जुलाई, 2017 तक 26,548 ग्राम पंचायतों को इससे जोड़ दिया गया है।</p> <p>वर्ष 2017-18 के अंत तक, ऑप्टिकल फाइबर पर उच्च गति ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी 1,50,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में उपलब्ध होगी, जिसमें कम दरों पर वाईफाई हॉटस्पॉट और डिजिटल सेवाओं तक पहुंच शामिल होंगे</p>
----	--	---	--	---	---

49	सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई)	ग्रामीण विकास मंत्रालय	11 .10. 2014	आदर्श ग्राम का विकास करके गांव में सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक और इन्फ्रास्ट्रक्चर संबंधी विकास करना	<p>पहले चरण में माननीय संसद सदस्यों ने 703 ग्राम पंचायतों (GP) को गोद लिया था और इस स्कीम के दूसरे चरण के अंतर्गत 382 ग्राम पंचायतों को गोद लिया गया था और अभी तक और 47 ग्राम पंचायतों को गोद लिया गया है</p> <p>एसएजीवाई पोर्टल पर राज्यों द्वारा अपलोड की गई रिपोर्टों के अनुसार कार्यान्वयन किए जाने के लिए योजना के अनुसार 40962 परियोजनाओं में से 2196 परियोजनाएं पहले से ही पूरी की जा चुकी हैं या अभी इन पर काम चल रहा है।</p>
50	श्याम प्रसाद मुखर्जी रूरन मिशन	ग्रामीण विकास मंत्रालय	21.2 .2016	इस मिशन का लक्ष्य अगले 3 वर्षों में देशभर में ऐसे 300 रूरन विकास समूहों का निर्माण करना है। रूरन समूहों के लिए फंडिंग सरकार की विभिन्न	<p>28 राज्यों ने अपने एकीकृत समूह कार्ययोजनाओं को पूरा कर लिया है और 90 समूहों में चरण 1 के लिए निधियों का लाभ उठाया है।</p> <p>28 राज्यों और 5 संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा</p>

			<p>योजनाओं के माध्यम से क्लस्टर में कन्वर्ट की जाएगी।</p>	<p>89 क्लस्टरों की पहचान की गई है और इसकी मंजूरी मंत्रालय द्वारा दी गई है। यह वर्ष 2016 - 17 के लिए लक्षित समय से पहले पूरा हो गया है।</p> <p>चरण 1 और 2 के अंतर्गत मंजूर किए गए 189 क्लस्टरों में से 50 क्लस्टर जनजातीय क्लस्टर हैं और चरण 1 के अंतर्गत यह सभी 17 जनजातीय क्लस्टरों के मंजूर योजनाएं हैं।</p> <p>300 करोड़ रुपए की आवंटित धनराशि राज्यों को जारी की जा चुकी है और 600 करोड़ रुपए के कुल आवंटन के साथ आवंटन में 100 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।</p> <p>कृपया उपलब्धि पर नवीनतम आंकड़े अद्यतन करें?</p>
--	--	--	---	--

51	<p><b>प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) अपना घर अपनी छत (यू डी आर डी)</b></p>	<p>ग्रामीण विकास मंत्रालय और आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय</p>	<p>20 .11 .2016 पीएमएवाई ग्रामीण</p>	<p>प्रत्येक ग्रामीण गरीब व्यक्ति को घर प्रदान करना जिसमें अन्य सुविधाओं के साथ साथ अनिवार्य रूप से शौचालय भी होगा। वर्ष 2019 तक एक करोड़ घरों को बनाने का लक्ष्य है ऐसी एसईसीसी 2011 के आधार पर लाभार्थियों की पहचान की गई है।</p>	<p><b>पीएमएवाई ग्रामीण</b></p> <p>इस स्कीम में वर्ष 2016-17 में 15000 करोड़ रुपए का आवंटन बढ़कर वर्ष 2017-18 में 23000 करोड़ रुपए हो गया है।</p> <p>वर्ष 2016-17 से लेकर वर्ष 2018-19 तक 3 वर्षों में एक करोड़ घरों के निर्माण के लक्ष्य में से वर्ष 2016-17 के लिए 33% की वृद्धि करके 33 लाख का लक्ष्य कर दिया गया है। जनवरी 2017 में अतिरिक्त 11 लाख घरों को मंजूरी दी जा चुकी है।</p> <p>31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार राज्यों द्वारा आवास सॉफ्ट पर दिए गए विवरण के अनुसार 32.14 लाख घरों को पूरा कर लिया जाने की रिपोर्ट है जिसमें 8 लाख घरों को वास्तविक रूप से पूरा किया जा चुका है लेकिन नेटवर्क/ आईटी से संबंधित मामलों के कारण आवास सॉफ्ट पर उक्त का आंकड़ा अपलोड नहीं किया जा सका। राज्यों को उक्त आंकड़ों को आवास सॉफ्ट पर दर्शाने के लिए अतिरिक्त समय प्रदान किया गया है। वर्ष 2015-16 में पूरे किए गए घरों की संख्या वन 8.31 लाख थी।</p>
----	--	---	--------------------------------------	--	---

				<p>885 पीएमएवाई ग्रामीण घरों को 4 महीनों में पूरा किया गया।</p> <p>पहले 18 महीनों से लेकर 3 वर्षों की तुलना में घरों को पूरा करने का महत्वकांशी लक्ष्य 6 से 12 महीने बनाया गया है।</p> <p>निर्माण के विभिन्न चरणों पर घरों की भू-संदर्भित चित्र, समय और तारीख, स्टैंप लगी फोटोग्राफ की सहायता से सत्यापन में समय विलंब कम हुआ और इससे घरों का निर्माण तेजी से हुआ और कार्य की प्रगति स्वस्थ एवं प्रभावी मॉनिटरिंग हुई है। वित्तवर्ष 2016-17 के दौरान आवास ऐप का उपयोग करके सिर्फ तीन लाख से भी अधिक निरीक्षण का संचालन किया गया है।</p> <p>वर्तमान में एसईसीसी 2011 के अनुसार 4.06 करोड़ गृहस्थी में से 3.53 करोड़ गृहस्थी को ग्राम सभा द्वारा सत्यापित किया गया है और अपीलीय प्रक्रियाओं की समाप्ति के पश्चात 2.26 करोड़ घर वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र पाए गए हैं।</p>
			<p>क रुप से कमजोर समाज के वर्गों के संबंध में शहरी क्षेत्रों में आवास की मांग और पूर्ति में अंतर को कम करना आपके एवं शानदार घर प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास का लक्ष्य पूरा करने के लिए और निम्न एवं मध्यम आय समूह के लिए</p>	

			25.06.2015 पीएमएवाई शहरी		<p><b>पीएमएवाई शहरी</b></p> <p>पीएमएवाई शहरी स्कीम के अंतर्गत घरों के निर्माण के लिए अभी तक 18.75 घरों को मंजूरी दी गई है।</p> <p>वर्ष 2014 17 के दौरान वन 3.80 लाख घरों के निर्माण को मंजूरी दी गई है।</p> <p>पीएमएवाई शहरी स्कीम के अंतर्गत 2014 17 के दौरान 3.15 लाख घरों का निर्माण किया गया और चल रही स्कीम में 2004 से 2014 के दौरान 7.90 लाख घरों का निर्माण किया गया था।</p>
52	<b>दीनदयाल अंत्योदय योजना</b>	<b>ग्रामीण विकास मंत्रालय और आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय</b>	25.09.2014	इसका उद्देश्य लगभग 9 करोड़ अनुमानित सभी ग्रामीण गरीब गृहस्थी तक पहुंचना है और उन्हें सभी ग्रामीण गरीबों को स्वयं प्रबंधित संस्थानों में आयोजित करके संतुलित जीविका के अवसर प्रदान करना है और उनकी कौशल	<p>सभी 29 राज्य और 5 संघ राज्य क्षेत्र (दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर) वर्तमान में 556 जिलों में 3814 खंडों में इस मिशन का आयोजन कर रहे हैं। इस मिशन से यह आशा है कि वर्ष 2024 25 तक सभी ग्रामीण गरीब रहस्य लगभग 9 करोड़ को गरीबी से मुक्त किया जाएगा।</p> <p>वित्तवर्ष 2016 17 में 2 लाख अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण देने के लक्ष्य की तुलना में 1.32 लाख</p>

				<p>एवं क्षमताओं का निर्माण करना और और उनके गरीबी से बाहर आने तक सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों से उन्हें वित्त, जीविका सुविधाएं, परिलब्धियां और सेवाएं प्राप्त करने योग्य बनाना।</p>	<p>युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है जिनमें से 149000 अभ्यर्थियों को रोजगार मिल गया।</p> <p>इसी प्रकार दिनांक 30 जून 2017 तक 38057 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया था और 24103 को रोजगार प्रदान किया गया।</p>
53	<p><b>प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)</b></p>	<p>सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय</p>	25.06.2015	<p>सभी मौसम में अनुकूल रोड के माध्यम से कनेक्टिविटी प्रदान करना</p>	<p>इस योजना के शुरू होने से लेकर अभी तक, 178184 पात्र आवासों में से 161 876 आवासों 19.84 प्रतिशत को मंजूरी दी गई है जिनमें से 124 427 आवास (तकरीबन 70% ) 30 जून 2017 तक 513 882 किलोमीटर लंबाई की सड़क के साथ जोड़कर पीएमजीएसवाई के साथ जोड़ा गया है।</p> <p>वर्ष 2016-17 के दौरान कुल 7447 किलोमीटर पीएमजीएसवाई सड़क का रिकॉर्ड निर्माण किया गया।</p> <p>वर्ष 2015-17 के लिए प्रतिदिन 130 किलोमीटर सड़क के निर्माण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है क्योंकि पिछले 7 वर्षों में वार्षिक निर्माण दर का उच्चतम औसत है</p>

				<p>वर्ष 2016-17 के दौरान पीएमजीएसवाई सड़कों का 4744 सेवर किलोमीटर निर्माण करके वन वन चित्र वन आवासों को कनेक्टिविटी प्रदान की गई थी प्रतिदिन औसत 32 आवासों को कनेक्टिविटी प्रदान की गई पिछले 7 वर्षों में सबसे अधिक है।</p> <p>2016-17 के दौरान पीएमजीएसवाई के अंतर्गत एक नया वर्टिकल लॉन्च किया गया है जो 9 LW E राज्यों में 44 बुरी तरह प्रभावित lwe की जिलों में सभी मौसम में अनुकूल सड़कों के निर्माण के लिए । w e प्रभावित क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी परियोजना है और इसमें 157. 25 करोड़ की अनुमानित लागत के साथ नजदीकी जिलों में मिली रोड बनाए जाएंगे यह परियोजना मार्च 2020 तक पूरी की जाएगी</p> <p>वर्ष 2014-17 के दौरान वर्ष 2011-14 के दौरान औसतन 70 .5 किलोमीटर सड़क निर्माण की तुलना में प्रतिदिन 113 किलोमीटर सड़क निर्माण का कार्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत किया गया</p> <p>हरित प्रौद्योगिकी जैसे कोल्ड मिक्स, फ्लाइ ऐश, झूठ आदि जैसी हरित प्रौद्योगिकियों के साथ वर्ष 2016 17 में और वनवास 3 किलोमीटर सड़कों का</p>
--	--	--	--	---

					<p>निर्माण किया गया इसकी तुलना में वर्ष 2014 16 में 2634 किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ था जो कि 2012-14 में 1000 किलोमीटर से भी कम है।</p> <p>सड़क निर्माण की गुणवत्ता और गति के बारे में शिकायत दर्ज करने में पारदर्शिता और नागरिक सहभागिता लाने के लिए मेरी सड़क मोबाइल एप्प</p> <p>पांच राज्यों अर्थात असम राजस्थान छत्तीसगढ़ तेलंगाना और उड़ीसा में 10 दिनों में पीएमजीएसवाई सड़कों की मॉनिटरिंग के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी इसमें से 242 पीएमजीएसवाई सड़कों का निर्माण पूरा किया गया</p> <p>20 राज्यों को अधिसूचित किया गया है और उन्होंने ग्रामीण सड़क देखरेख नीति का संचालन शुरू कर दिया है</p>
54	जीर्णोद्धार और शहरी रूपांतरण के लिए अटल	आवास एवं शहरी गरीबी	25.06.2015	वर्ष वर्ष 2019 तक मिशन शहरों में सीवर व्यवस्था	

	<b>मिशन अमृत</b>	<b>उन्मूलन मंत्रालय</b>		<p>और जल निकासी नेटवर्कों का विस्तार गैर मोटर कृत परिवहन और खुला एवं अधिक स्थान प्रदान करने के साथ-साथ 20000000 से भी अधिक शहरी ग्रंथों को चलो उपलब्ध कराना</p>	<p>77678 करोड़ रुपए के परियोजना निवेश के साथ मिशन अवधि 33 वर्ष पहले 5 सभ्नी 500 मंजूर मिशन शहरों के लिए सर्विस लेवल इंप्रूवमेंट प्लान s l i p s 14000 करोड़ रुपए से भी अधिक मूल्य की परियोजनाओं का निष्पादन शुरू किया जा चुका है और बाकी की परियोजनाएं पेंटर और डीपीआर तैयार करने के स्तर पर है</p> <p>इस मिशन से लगभग 22 करोड़ शहरी जनसंख्या लाभान्वित होगी</p> <p>कृपया उपलब्धियों पर नवीनतम आंकड़ा अधिकतम करें</p>
55	<b>स्मार्ट सिटी मिशन</b>	<b>आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय</b>	25.06.2015	<p>समावेशी और संतुलित शहरी नियोजन एवं विकास के आधार पर सो शहरों में तथा उसके आसपास क्षेत्र आधारित विकास के माध्यम से जीवन गुणवत्ता के स्तर में सुधार करने के लिए आधारभूत अवसंरचना को सुनिश्चित करना</p>	<p>प्रतियोगिता के माध्यम से 98 शहरों को पहचान की गई</p> <p>98 शहरों में से 7 शहरों को प्रतियोगिता के माध्यम से वित्त पोषण किया गया</p> <p>इन 7 शहरों के लिए 133 368 करोड़ रुपए का निवेश को मंजूरी दी गई</p> <p>इस परियोजना से कुल 1.2 करोड़ जनसंख्या लाभान्वित होगी</p>

					<p>25 जून 2017 तक 35,000 करोड़ रुपए के मूल्य की परियोजनाएं पूरी की जाएगी</p> <p>उपलब्धियों पर नवीनतम आंकड़े को अद्यतन कीजिए</p>
56(A)	<b>स्वच्छ भारत अभियान</b>	<b>पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय</b>	2.10.2014	स्वच्छ एवं स्वस्थ भारत का महात्मा गांधी का सपना पूर्ण करना	<p>इस मिशन के शुरू होने से लेकर अभी तक 4.52 करोड़ गृहस्थ शौचालय का निर्माण किया गया</p> <p>217 210 गांवों 155 0 और पांच राज्यों को 31 जुलाई 2017 तक की स्थिति के अनुसार खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है</p> <p>शौचालय के लिए प्रोत्साहन राशि को बढ़ा कर 12000 रूपय कर दिया गया है</p> <p>दिनांक 2 अगस्त 2014 से लेकर 210 2015 तक की अवधि के दौरान 80 लाख शौचालयों का निर्माण किया गया 60 लाख शौचालयों की प्रत्याशा थी</p> <p>वर्ष 2014 15 के लिए निजी लैट्रिन के लिए 50 लाख के वार्षिक लक्ष्य की तुलना में 5854987 बैटरी लो का निर्माण किया गया था फोकी लक्ष्य का 117 प्रतिशत की उपलब्धियों</p>

				<p>वर्ष 2012 13 और वर्ष 2013 14 में कर्म 64555 508918 600095 का निर्माण किया गया था जबकि दूसरी ओर एनडीए सरकार के पहले 2 वर्षों में वर्ष 2014 15 और वर्ष 2015 16 कर्मचारी 58 पॉइंट 54 लाख और 9 7.73 ब्लाक शौचालय का निर्माण किया गया और 29 फरवरी 2015 तक</p> <p>ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के को स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थलों एसआईपी वैश्विक मानकों के अनुसार स्वच्छता का उच्चतम स्तर बात करेंगे इनमें से 20 स्थलों को चरण 1 और चरण 2 में चयनित किया गया है</p> <p>पांच राज्यों में 52 जिलों में गंगा नदी के तटों पर बस 4480 गांव को खुले में शौच मुक्त गांव घोषित किया गया</p>
56 (B)	<b>स्वच्छ विद्यालय</b>	<b>मानव संसाधन विकास मंत्रालय</b>	सभी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में शौचालय बनाना	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 15.8.2014 से 15.8.2015 के बीच 2.61 लाख विद्यालयों में 4.17 लाख शौचालय बनाए गए</li> <li>• 11.21 लाख सरकारी स्कूलों में 13.77</li> </ul>

					करोड़ विद्यार्थी के पास अब शौचालय
57	<b>नमामि गंगे</b>	जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा पुनरोद्धार मंत्रालय	10.7.201 4	समग्र तरीके से गंगा नदी को साफ करने और संरक्षित करने के प्रयासों को समेकन करना	<p>मई 2014 से इस कार्यक्रम के लिए 12423.63 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है।</p> <p>कुल स्वीकृत धनराशि में से 2618.42 करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं।</p> <p>12423.63 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत 155 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी। अभी तक 41 परियोजनाएं की गई हैं।</p> <p>155 परियोजनाओं में से 75 परियोजनाओं के लिए 932.84 एमएलडी नए शिविर उपचार संयंत्रों (एसटीपी) का निर्माण करने की मंजूरी दी गई थी। गंगा और यमुना नदी में प्रदूषण को कम करने के लिए विद्यमान 1091 एमएलडी के पुनर्वास और 4031 किलोमीटर सीवर नेटवर्क के लिए मंजूरी दी गई थी। इन परियोजनाओं की कुल मंजूर राशि 10289.43 करोड़ रुपए है जिनमें से 2191.43 करोड़ रुपए पहले ही खर्च किए जा चुके हैं। 14 परियोजनाएं पूरी की जा</p>

				<p>चुकी हैं।</p> <p>वर्तमान में 20 नगरों में से 1031 एमएलडी की उपचार क्षमता का निर्माण करने के लिए 661 नगर निगम सीवरेज प्रबंधन परियोजनाएं चल रही हैं।</p> <p>1109 गंभीर रूप से प्रभावित उद्योगों का निरीक्षण किया गया और इनमें से 597 की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। निर्धारित मापदंडों का अनुपालन ना करने के कारण 2700 जी पी आई को बंद कर दिया गया है। 109 इकाइयों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।</p> <p>4076 गांव को खुले में शौचमुक्त घोषित कर दिया गया है जिनमें से 4291 गांव नदी प्रवाह के मुख्य भाग पर स्थित है।</p> <p>15.27लाख व्यैक्तिक लैट्रिनों के लक्ष्य की तुलना में लगभग 1 1.4 लाख व्यक्तिक लैटरिनों का निर्माण किया जा चुका है।</p> <p>गंगा ग्राम गांव में ग्रामीण स्वच्छता के लिए एक नई पहल शुरु की गई है और पेयजल एवं</p>
--	--	--	--	--

				<p>स्वच्छता मंत्रालय को स्वच्छ भारत (ग्रामीण) के लिए 578 करोड़ पर जारी किए गए हैं।</p> <p>110 स्थानों पर मैनुअल जल गुणवत्ता मॉनिटरिंग और 40 स्थानों पर रियल टाइम जल गुणवत्ता मॉनिटरिंग शुरू की गई है।</p> <p>जैव विविधता कार्यक्रम के अंतर्गत नरोरा और सारनाथ में कछुओं के लिए दो बचाव एवं राहत केंद्र खोले गए हैं और पहली बार गंगा नदी के पूर्ण मार्ग में गंगा डॉल्फिन सहित जलीय जंतुओं को समेकित बेसलाइन सर्वेक्षण चल रहा है।</p> <p>नदी में पर्याप्त प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए 10 केंद्रीय मंत्रालयों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। विभिन्न उपभोग क्षेत्रों में ही प्रवाह को ठीक करने और जल उपयोग की गुणवत्ता को सुधारने के लिए कई कदम उठाए गए हैं।</p> <p>गंगा के किनारे वनीकरण की योजना बनाई गई है। जिसमें प्राकृतिक, कृषि एवं शहरी स्थान पर पौधारोपण, संरक्षण हस्तक्षेप जैसे आद्रभूमि मृदा एवं जल प्रबंधन /अनुसंधान, जागरूकता एवं</p>
--	--	--	--	---

				<p>क्षमता निर्माण आदि शामिल हैं। वर्ष 2016 17 के लिए 34668 का उन्नत मृदा कार्य और 136759 पौधों की बुआई की योजना बनाई गई है। इसी प्रकार वर्ष 2017 के दौरान उत्तराखंड के 7 जिलों में चिकित्सकीय पौधों सहित 8046 हेक्टेयर का उन्नत मृदा कार्य किया गया है।</p> <p>घाट और नदी की सतह पर तैरने वाले कठोर अपशिष्ट को एकत्र करने के लिए सतह की सफाई और कूड़ा उठाने वालों की सहायता से इसके निपटान का कार्य 11 स्थानों पर शुरू किया गया है।</p> <p>पुराने घाटों तथा शमशान घाटों के नवीनीकरण के लिए 1391.30 करोड़ रुपए की लागत से 60 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी जिनमें से 24 परियोजनाओं को 1800 करोड़ रुपए की लागत से पूरा कर लिया गया है।</p> <p>27.55 करोड़ रुपए की लागत से दो नदी फ्रंट विकास परियोजना को मंजूरी दी गई है अभी तक तीन परियोजना पर 128.11 करोड़ रुपए पहले ही व्यय किए जा चुके हैं।</p>
--	--	--	--	---

				<p>5 करोड़ की लागत से घाट की सफाई के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी गई है इस परियोजना पर 2.9 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं।</p> <p>पांच संस्थागत विकास (गैर इंफ्रास्ट्रक्चर) परियोजनाओं के लिए 250 82 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर की गई है इन परियोजनाओं में 16 . 87 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं।</p> <p>88.71 करोड़ रुपए की लागत से 11 सहायता /अनुसंधान एवं अध्ययन परियोजना को मंजूरी दी गई है। 2 परियोजनाएं पूरी कर ली गई है और इन परियोजनाओं पर 53.61 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं।</p> <p>यूएनडीपी सहायता के अंतर्गत ग्रामीण स्वच्छता की एक परियोजना को 127.83 करोड़ रुपए की लागत से मंजूरी दी गई है इन परियोजनाओं पर 5 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा चुकी है।</p>
--	--	--	--	---

58	<p><b>मिशन इन्द्रधनुष</b></p> <p>तीव्र मिशन इन्द्रधनुष अक्टूबर 2017 से शुरू किया जाएगा</p>	<p>स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय</p>	25.12.2014	<p>नियमित टीकाकरण से छूटे हुए बच्चों तक पहुंचना।</p> <p>मिशन इन्द्रधनुष का उद्देश्य वर्ष 2020 तक कम से कम 90% बच्चों को भारत में पूर्ण टीकाकरण प्रदान करना है।</p> <p>शहरी क्षेत्रों और निम्न टीकाकरण कवरेज के अन्य पॉकेट पर ध्यान वर्ष 2018 तक पूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य।</p>	<p>मिशन इन्द्रधनुष के अंतर्गत 2.47 करोड़ से भी अधिक बच्चों और लगभग 67 लाख गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण किया गया है।</p> <p>66.5 लाख पैकेटों और 2.8 करोड़ ज़िंक की गोलियों के साथ लगभग 71 लाख विटामिन ए की खुराकों को वितरित किया गया है।</p> <p>पूर्ण टीकाकरण की कवरेज में 1% की वार्षिक वृद्धि से मिशन इन्द्रधनुष में एकीकृत बाल स्वास्थ्य एवं टीकाकरण सर्वेक्षण</p> <p>(एनआईसीएचआईएस) की रिपोर्ट के अनुसार टीकाकरण की कवरेज में 6.7 की वार्षिक दर से विस्तार किया है।</p> <p>वर्तमान में मिशन इन्द्रधनुष के अंतर्गत</p>
----	--	---	------------	--	---

				<p>4 चरणों में 35 राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में 528 जिलों को कवर किया गया।</p> <p>गहन इंद्रधनुष मिशन के अंतर्गत 128 जिलों 17 शहरी क्षेत्र और उत्तर पूर्वी राज्य के 52 जिलों को लक्ष्य बनाया जाएगा ।</p>	
	<p><b>नया टीका प्रस्तुत किया गया</b></p>		<p>नवंबर 2015</p>	<p>इनएक्टिवेटीड् पोलियो टीका (आईपीवी ) -</p> <p>वर्ल्ड पोलिओ एंड गोम्स स्ट्रेटेजी के अनुसरण में 6 राज्यों में आईपीवी प्रस्तुत किया गया था और जून 2016 तक देशभर में विस्तार किया गया। 6 और 14 सप्ताह की आयु में आईपीवी के दो खंडों में खुराक प्रदान की जाती हैं।</p>	<p>जून 2017 तक इस योजना के शुरू होने से लेकर अभी तक लगभग 2 . 27 करोड़ आईपीवी की खुराक बच्चों को प्रदान की जा चुकी है ।</p>

			मार्च 2016	<p>रोटावायरस टीका</p> <p>रोटावायरस के कारण होने वाले डायरिया के भार को कम करने के लिए रोटवायरस वैक्सीन आंध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा में प्रस्तुत की गई और इसे असम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और त्रिपुरा में दिनांक 18 फरवरी 2017 को भी लागू कर दिया गया है। यह टीका 6, 10 और 14 सप्ताह की आयु में प्रदान किया जाता है।</p>	<p>इस योजना के चालू होने से लेकर अभी तक जून 2017 तक बच्चों को लगभग 68.5 लाख रोटवायरस टीके की डोज़ प्रदान की जा चुकी है ।</p>
59	<p><b>प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना</b></p>	<p><b>रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय</b></p>		<p>गरीबों को सस्ती दवा की उपलब्धता</p>	<p>दिनांक 28.7.17 तक, 31 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में 2060 प्रधानमंत्री भारतीय</p>

	(पीएमबीजेपी)	औषधि विभाग			<p>जन औषधि केंद्र (पीएमबीजेपी) कार्य कर रहे हैं।</p> <p>वर्ष 2017 -18 में 988 जन औषधि केंद्र खोले गए हैं।</p> <p>इस स्कीम के उत्पाद में 600 से भी अधिक दवाइयों और 154 सर्जिकल सहायक उपकरण और सभी थेरेपी श्रेणियों को कवर करने वाली उपभोग योग्य वस्तुओं को शामिल करके विस्तार किया गया है।</p> <p>कृपया उपलब्धियों का नवीनतम आंकड़ा अद्यतन करें</p>
60	नई मंजिल	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	15 8 2015	प्रमाणपत्र के साथ औपचारिक शिक्षा और	वर्ष 2016 17 में 23 राज्यों में शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण के लिए 69,840

				<p>कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके 17 से लेकर 35 वर्ष की आयु समूह के ऐसे अल्पसंख्यक युवा को लाभ पहुंचाना जो स्कूल ड्रॉपआउट हैं या जिन्होंने मदरसों जैसे सामुदायिक शिक्षा संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त की है।</p>	<p>प्रशिक्षकों को आवंटित किया गया है।</p> <p>प्रबंधन, एमआईएस और स्कीम की मॉनिटरिंग के लिए मंत्रालय के भीतर परियोजना प्रबंधन यूनिट (पी एम यू) की स्थापना की गई</p> <p>इस मंत्रालय ने संयुक्त नियंत्रक, सहायक उपकरण खाता एवं लेखा प्रशिक्षण प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय को 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर की धनराशि के डी एल आई के पहले प्रतिपूर्ति भुगतान के दावे को प्रस्तुत किया है जिसे मंजूरी प्रदान की गई है और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक को भेजा गया है।</p>
61	<b>उस्ताद</b>	<b>अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय</b>	14 05 2015	दिनांक 14 मई 2015 को वाराणसी में उस्ताद (विकास के लिए परंपरागत	मंत्रालय ने राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के संस्थानों को अपने साथ जोड़ा है, जिनमें राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी

			<p>कला एवं शिल्पों में कौशल एवं प्रशिक्षण उन्नयन) इस स्कीम का उद्देश्य परंपरागत दस्तकार और शिल्पकारों की क्षमता निर्माण करके परंपरागत कलाओं एवं शिल्पों का मानकीकरण और उनका अभिकल्प विकास और बाजार संबंध स्थापित करके परंपरागत कौशल की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना।</p>	<p>संस्थान (एनआईएफटी), राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (एनआईडी) और भारतीय पैकेजिंग संस्थान (आईआईपी) शामिल है। महत्वपूर्ण संस्थाओं को विभिन्न समूहों में डिजाइन हस्तक्षेप, उत्पाद श्रृंखला विकास, पैकेजिंग, प्रदर्शनियों, फैशन शो और प्रचार-प्रसार, बिक्री बढ़ाने के लिए ई-विपणन पोर्टल के साथ सहयोग स्थापित करना और ब्रांड निर्माण के क्षेत्र में कार्य करने के लिए शामिल किया गया है।</p> <p>मंत्रालय ने जामदानी, स्टोन कार्विंग, बनारस ब्रोकेड और लकड़ी के खिलौने की चार शिल्पों के प्रोटोटाइप लॉन्च किए हैं, जिन्हें वाराणसी में एनआईएफटी और एनआईडी की सहायता से अल्पसंख्यकों द्वारा विकसित किया जा रहा है।</p>
--	--	--	--	---

					<p>वर्ष 2015-16 के लिए 17 .01 करोड़ रूपए के निर्धारित बजट में से 16.90 करोड़ रूपये जारी किए गए थे।</p> <p>मंत्रालय ने उस्ताद स्कीम को प्रोत्साहन देने, उसकी ब्रांडिंग करने एवं प्रचार प्रसार करने के लिए हुनर हाट के रूप में विशाल प्रदर्शनियों का आयोजन करने का निर्णय लिया है। हुनर हाट अल्पसंख्यक समुदाय के दस्तकारों और शिल्पियों को उनकी परंपरागत कला एवं शिल्पों का प्रदर्शन करके बढ़ते बाजार में अवसरों का फायदा उठाने के योग्य बनाना और प्रोत्साहित करने के लिए हुनर हाट का आयोजन किया जाता है। अभी तक दो हुनर हाट का आयोजन किया जा चुका है (1) इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, नई दिल्ली दिनांक 14 से 27 नवंबर 2016 और (2) स्टेट इम्पोरिया कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली, दिनांक 11 से 26 फरवरी</p>
--	--	--	--	--	--

					2017  मंत्रालय ने परंपरागत कला एवं शिल्प में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 38 परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए) को पैनल में शामिल किया है। वर्ष 2016 - 17 के दौरान मंत्रालय ने 11 राज्यों में पीआईए को 16200 प्रशिक्षुओं के लिए प्रदर्शनी का आयोजन करने के लिए एन एम डी एफ सी को 1.74 करोड़ रुपये सहित 19.77 करोड़ धनराशि जारी की है।
62	<b>पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना (पीडीयूएसजेवाई)</b>	<b>श्रम एवं रोजगार मंत्रालय</b>	श्रम निरीक्षण की सूचना एकत्रित करना और एकीकृत वेब पोर्टल के माध्यम से इस का	कृषि एवं गैर कृषि दोनों क्षेत्रों में 42% तक न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी की गई है। इससे 55 लाख अतिरिक्त कामगारों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा।	

			<p>प्रवर्तन करना इससे श्रम निरीक्षण में पारदर्शिता और जवाब देयता की स्थापना होगी</p>	<p>सातवां वेतन आयोग : 50 लाख कर्मचारियों और 35 लाख पेंशनभोगियों को लाभ प्रदान किया गया।</p> <p>बोनस (संशोधन) का भुगतान अधिनियम 2015, बोनस के भुगतान के लिए पात्रता की सीमा को ₹10000 प्रतिमाह से बढ़ाकर 21000 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है।</p> <p>श्रम सुविधा पोर्टल कुल 19,82,407 यूनिक श्रमिक पहचान संख्या एल आई एन उत्पन्न किए गए और 12 जून 2017 तक 8 केंद्रीय श्रम कानून के अंतर्गत 5747 सामान्य वार्षिक रिटर्न जमा की गई। ईपीएफओ और ईएसआईसी के अंतर्गत सामान्य पंजीकरण के लिए सुविधा और ईपीएफओ और ईएसआईसी के लिए</p>
--	--	--	--	--

				<p>मासिक सामान्य इलेक्ट्रॉनिक चालान शहर रिटर्न पीसीआर पोर्टल पर उपलब्ध है। हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली को शामिल हैं। यह पोर्टल अंग्रेजी सहित 11 भाषाओं में बहुभाषीय इंटरफेस पर उपलब्ध है।</p> <p>श्रमिकों को स्थाई पहचान प्रदान करने के लिए यूनिक लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर आवंटित किया गया है। दिनांक 15 -12 -2016 तक ईपीएफओ ने अपने सदस्यों को लगभग 9.64 करोड़ यू ए एन प्रदान किया है और इनमें से 3.03 करोड़ सदस्यों ने अपने मोबाइल नंबर का प्रयोग करके यह नंबर सक्रिय किया है और यह ऑनलाइन सुविधाओं से लाभ प्राप्त कर रहे हैं। डिजिटल रूप से मंजूर केवाईसी की संख्या 7.05 करोड़ है।</p>
--	--	--	--	---

					<p>विवरणी, श्रम पंजीकरण, निरीक्षण आदि से कुछ उद्योगों को छूट प्रदान करने के लिए श्रम कानूनों में संशोधन।</p> <p>फैक्ट्री अधिनियम 1948, में संशोधन जिससे कि महिलाओं को नाइट शिफ्ट में कार्य करने की गति प्रदान की जा सके। ओवरटाइम के घंटों को बढ़ाया जा सके।</p> <p>अधिक अप्रेंटिस को सुनिश्चित करने के लिए अप्रैन्टिस अधिनियम में संशोधन किया गया। स्टाइपेंड को न्यूनतम मजदूरी से जोड़ा गया।</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>1 वर्ष में कॉमन ऑनलाइन रिटर्न की सुविधा</p> <p>वस्तुओं और सेवाओं के मानकों में सुधार करने के लिए बीआईएस कानूनों में सुधार।</p> <p>राष्ट्रीय करियर सेवा परियोजना एक ही प्लेटफॉर्म पर नियोक्ताओं, प्रशिक्षकों और बेरोजगार व्यक्तियों को एक साथ लाना। पोर्टल के माध्यम से 3.9 करोड़ नौकरी ढूंढने वालों, वो 14.8 लाख नियोक्ताओं और 6 लाख रिक्तियों को मोबाइल किया गया। एनसीएस के अंतर्गत 640 से भी अधिक रोजगार मेलों का आयोजन किया गया।</p>
63	<b>प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई)</b>	<b>श्रम एवं रोजगार मंत्रालय</b>	09.08.2016	वर्ष 2016 अगस्त माह से नए रोजगार के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहन देने के लिए प्रधानमंत्री	दिनांक 31- 7- 2017 तक कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या 3,02,752 है

				<p>रोजगार प्रोत्साहन योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसमें सरकार 3 वर्षों की अवधि के लिए नए कर्मचारियों के लिए ईपीएस का 8.33 प्रतिशत नियोक्ता का अंशदान का भुगतान करेगी। इस स्कीम के अंतर्गत 2.5 लाख नए कर्मचारियों को कवर किया जा चुका है।</p>	<p>और कवर किए गए प्रतिष्ठानों की संख्या 6588 है।</p>
64	<b>ईशान विकास</b>	<b>मानव संसाधन विकास मंत्रालय</b>	<p>उत्तर पूर्वी राज्यों के प्रतिभावान विद्यार्थियों को एक्सपोजर विजिट प्रदान करने के लिए आईआईटी, एन आईटी, एनआईएफटी</p>	<p>इशान विकास</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• इस कार्यक्रम के तहत दिसंबर 2014 से जुलाई 2017 तक, कुल 372 अभियंत्रण छात्र (260 लड़के और 112 लड़कियां) शामिल किये गए थे।</li> <li>• वर्ष 2014 से 2016 के अंत तक आठ पूर्वोत्तर राज्यों के कुल 1637 स्कूली छात्र इस कार्यक्रम</li> </ul>	

			में इंटरनेशिप		से लाभान्वित हुए।
65	<b>राष्ट्रीय अकादमिक निक्षेपागार</b>	<b>मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय</b>	09.09.2016	डिजिटल इंडिया के विजन के साथ सुरक्षा डिपॉजिटरी ऑनलाइन के पैटर्न पर स्कूल लर्निंग सर्टिफिकेटों, डिग्रियों और उच्च शिक्षा संस्थानों के अन्य अकादमिक अवार्डों के लिए डिजिटल डिपॉजिटरी का विकास करना।	प्रमाण पत्र, मार्कशीट से छेड़छाड़ और जालसाजी जैसी संपूर्ण प्रथाओं का उन्मूलन करना और वेलिडेशन को सुविधाजनक बनाना  कृपया उपलब्धि पर नवीनतम आंकड़े अद्यतन कीजिए।
66	<b>ज्ञान</b>	<b>मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय</b>	30.11. 2015	उच्च शिक्षा और अनुसंधान में गुणवत्ता सुधार करने का लक्ष्य	32 देशों के साथ पहले से ही पार्टनरशिप की जा चुकी है।  इस स्कीम के अंतर्गत अभी तक 801 पाठ्यक्रम प्रस्तावों को मंजूरी दी जा चुकी है इन कोर्सों में से लगभग 631 पाठ्यक्रमों को आयोजित किया गया है।

					<p>वर्ष 2015 - 16 और 2016 - 17 के दौरान इस स्कीम के लिए क्रमशः 33 करोड़ और 20 करोड़ रुपए जारी किए गए थे।</p> <p>कृपया उपलब्धियों पर नवीनतम आंकड़े को अद्यतन कीजिए</p>
67	<p><b>अटल नवाचार मिशन एआईएम और स्व-रोजगार और प्रतिभा उपभोग (सेतु)</b></p>	<p><b>नीति आयोग</b></p>	<p>दिनांक 24 फरवरी 2016 को मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर</p>	<p>स्व-रोजगार और प्रतिभा उपभोग (सेतु) सहित अटल नवाचार मिशन (एआईएम) नवाचार और उद्यमशीलता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार का एक प्रयास है। इसका उद्देश्य विश्वस्तरीय नवाचार केंद्रों को बढ़ावा देने के लिए एक प्लेटफार्म के रूप में कार्य करना है। इसका कार्य क्षेत्र बड़ी चुनौतियां,</p>	<p>अटल टिकरिंग प्रयोगशालाओं की स्थापना - दिसंबर 2016 में 257 स्कूलों को एटीएल अनुदान प्रदान किया गया था।</p> <p>अटल इंक्यूबेशन केंद्र की स्थापना- 60 चुने गए आवेदन अंतर मंत्रालयी समूह की सिफारिश के आधार पर चयनित आवेदकों पर अंतिम राउंड में SSC द्वारा विचार किया जाएगा।</p>

				<p>स्टार्टअप व्यवसाय और अन्य स्वरोजगार की गतिविधियां विशेष रूप से प्रौद्योगिकी आधारित क्षेत्रों में स्वरोजगार की गतिविधियों को बढ़ावा देना है।</p>	<p>स्थापित किए गए इंक्यूबेशन केंद्रों को सहायता बढ़ाना, अनुदान प्राप्त करने के लिए 17 शीर्ष आवेदकों में से 6 को चुना गया है। ईआईसी को सहायता बढ़ाने के लिए विस्तृत एमओए पर कार्य किया जा रहा है।</p> <p>अटल ग्रैंड चैलेंज भारत की चुनौतियां के लिए कुशल, आरोही, लागत प्रभावी, विश्व स्तरीय समाधान प्रदान करने के लिए, Grand चैलेंज संचालित करने के लिए उचित क्षेत्रों का मूल्यांकन वर्तमान में किया जा रहा है।</p>
68	<p><b>नेशनल इनिशियेटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशन (निधि)</b></p>	<p><b>विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय</b></p>	06..09.2016	<p>नेशनल इनिशियेटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशन (निधि) विज्ञान आधारित और प्रौद्योगिकी आधारित विचारों और नवाचारों के पोषण को सफल स्टार्टअप में</p>	<p>वर्ष 2016-17 के दौरान SINE, IIT मुंबई पुणे में कार्यक्रम प्रबंधन इकाई सहित स्थापना के लिए 10 निधि प्रयास केंद्रों को मंजूरी दी गई है। यह प्रयास केंद्र 10 करोड़ रुपए तक की प्रोटोटाइपिंग अनुदान के साथ 100 नवाचारकों का समर्थन करेंगे। एनसीएल,</p>

				<p>परिवर्तित करने के लिए परिकल्पित और विकसित एक प्रतिष्ठित कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और लक्ष्यों के अनुरूप है और इसका मुख्य लक्ष्य संपत्ति एवं रोजगार सृजन के माध्यम से सामाजिक आर्थिक विकास के उद्देश्य से नवाचार आधारित उद्यमशील वातावरण का निर्माण करना है।</p>	<p>पुणे में प्रौद्योगिकी व्यापार इनक्यूबेटर में कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के साथ स्थापना के लिए 10 निधि की आई आर केंद्रों की स्थापना को मंजूरी दी गई है। यह डीआईआर केंद्र 100 विद्यार्थी उद्यमियों को सहायता प्रदान करेंगे। राष्ट्रीय विशेषज्ञ सलाहकार समिति ने 15 निधि टीबीआई और 6 निधि सी ओ ई की स्थापना करने की सिफारिश की है। निधि टीबीआई 300 उद्यमशील उद्यमों की क्षमता वाला संचयी इंक्यूबेशन का निर्माण करेगा। इनक्यूबेटर में प्रारंभिक निवेश के प्रारंभिक चरण प्रदान करने के लिए प्रत्येक को 10 करोड़ रुपए की बढ़ी हुई प्रारंभिक सहायता के साथ 6 टीबीआई निधि को मंजूरी दी गई है।</p> <p>नवाचार के लिए सहायक वातावरण का निर्माण करने, स्टार्टअप इंक्यूबेशन और उद्यमशीलता को समृद्ध बनाने के लिए निधि कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यकलापों</p>
--	--	--	--	--	--

				<p>को बढ़ाने की योजना है। इसमें महिला उद्यमी सशक्तिकरण कार्यक्रम नवाचारी विचार कार्यक्रमों और Grand चुनौतियों के कार्यक्रमों को अधिक संख्या में समर्थन प्रदान करने की योजना प्रस्तावित है।</p> <p>सितंबर 2016 से 10 करोड़ रुपए तक के प्रोटोटाइपिंग ग्रांड के साथ नव आचार्य को को सहायता प्रदान करने के लिए 10 प्रयास केंद्रों की स्थापना की गई है इन केंद्रों ने प्रोटोटाइप अनुदान प्रदान करके 54 नवाचार को सहायता प्रदान की है 10 निधि उद्यमशीलता इन रेजिडेंस केंद्रों की स्थापना की गई है इन एआईआर केंद्र बने छात्रवृत्ति सहायता प्रदान करके 61 विद्यार्थी उद्यमियों को सहायता प्रदान की है DSP 15 निधि TV आई प्रद्योगिकी व्यापार इनक्यूबेटर और 6 सियोल उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए</p>
--	--	--	--	---

				<p>सहायता प्रदान कर रहा है। 8 टीबीआई ने नवाचारों को प्रारंभिक निवेश प्रारंभिक चरण के धन प्रदान करने के लिए प्रत्येक को 10 करोड़ रुपए की बड़ी हुई धनराशि प्रदान करके सहायता की DSP द्वारा सहायता प्रदान टीबीआई में दो निधि एक्सीलेटर की मंजूरी की गई है।</p> <p>नवाचार खोज और विकास कार्यक्रम के अंतर्गत इंडिया इनोवेशन ग्रोथ कार्यक्रम 2.0 के अंतर्गत विश्वविद्यालय चुनौती और मुक्त नवाचार के अंतर्गत नव आचार्य को को की पहचान की गई है और निवेश और मेंटरिंग सहायता प्रदान की जा रही है महिला उद्यमियों की पहचान और सहायता के लिए महिला उद्यमशीलता एवं सशक्तिकरण कार्यक्रम पर काम किया जा रहा है</p>
--	--	--	--	--

69	वन रैंक वन पेंशन	रक्षा मंत्रालय		भूतपूर्व सैनिकों और रक्षा परिवार पेंशनभोगियों की पेंशन में समानता	<p>इस मुद्दे को चार दशकों के बाद सुलझाया गया और प्रधानमंत्री द्वारा घोषणा की गई।</p> <p>30.4.2017 तक की स्थिति के अनुसार (10. 7. 2017 तक आंकड़े संकलित) 20,39,934 भूतपूर्व सैनिको/परिवार पेंशनभोगियों और 15,93,125 भूतपूर्व सैनिकों को ओआरओपू बकाया की पहली और दूसरी किस्त के रूप में क्रमशः 4156.59 करोड़ रुपए और 2385 .33 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है।</p> <p>इसके अतिरिक्त, ओआरओपी की तीसरी किस्त के रूप में 15,13,524 भूतपूर्व सैनिकों को 2,250.09 करोड़ रुपये का भुगतान भी किया जा चुका है।</p>
70	सुगम्य भारत	सामाजिक	3.12. 2015	इसका लक्ष्य जुलाई	यह योजना दिव्यांग लोगों के लिए

	<b>अभियान</b>	<b>न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय</b>		2018 तक राष्ट्रीय राजधानी और सभी राज्यों की राजधानियों में सभी सरकारी भवनों में कम से कम 50% भवनों को पूर्ण सुगम्य बनाना है।	प्रतिष्ठित जीवन को सुनिश्चित कर रही है।  6 लाख निशक्त व्यक्तियों सहायक यंत्र एवं उपकरण वितरण के लिए विशेष कैंप का आयोजन।
--	---------------	---	--	--	--

\*\*\*\*



